घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 249- शुक्रवार 10- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मिली नई गति

रक्षा,ऊर्जा,शिक्षा और प्रौद्योगिकी सहित 18 प्रमुख समझौते हुए

नई दिल्ली,09 जुलाई 2026। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत गुरुवार को रक्षा, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा विशेषकर नाभिकीय ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, शिक्षा, कौशल विकास, खनन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक विरासत सहित विभिन्न क्षेत्रों में 18 महत्वपूर्ण समझौतों और पहलों को अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मेलबर्न में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ सार्थक वार्ता की। वार्ता के नतीजों के तहत अब आस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियन की सप्लाई होगी। रक्षा क्षेत्र में सहयोग में दोनों देशों ने कई नए विषयों को शामिल किया है।

दोनों नेताओं ने वार्ता के दौरान भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई मजबूत प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में बताया,'हमने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते यानी सीईसीए पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है। 'प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में दोनों देशों की वैश्विक मुद्दों पर राय भी सामने रखी। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मानते हैं कि आतंकवाद केवल किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई साझा और संकल्प अटूट है। उन्होंने कहा कि हमारा यह भी मानना है कि विश्व के अनेक भागों में चल रहे तनावों और युद्धों का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। पूरे हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश मिलकर शांति,स्थिरता, नौवहन की स्वतंत्रता और नियम आधारित व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौतों में संयुक्त रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग घोषणा का नवीनीकरण शामिल है। इसके तहत सैन्य अंतर-संचालन क्षमता, समुद्री क्षेत्र जागरूकता,रक्षा उद्योग,साइबर सुरक्षा,आतंकवाद रोधी सहयोग, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप,ऊर्जा सुरक्षा पर संयुक्त वक्तव्य,भारत-ऑस्ट्रेलिया असैन्य परमाणु समझौते के प्रशासनिक प्रबंध को अंतिम रूप तथा साइबर, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी (पीएसीटीएस) पर भी सहमति बनी।

ऑस्ट्रेलिया लौटाएगा भारत की तीन प्राचीन धार्मिक धरोहर

भद्रकाली,नंदी और कार्तिकेय की दुर्लभ प्रतिमाएं होंगी स्वदेश वापस

भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी तीन दुर्लभ प्राचीन धार्मिक कलाकृतियां जल्द ही ऑस्ट्रेलिया से भारत वापस लौटेंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए द्विपक्षीय सहयोग के तहत इन धरोहरों की सम्मानपूर्वक वापसी की जाएगी। वापस लाई जाने वाली कलाकृतियों में देवी भद्रकाली की आकृति वाला धातु का त्रिशूल,भगवान शिव के वाहन नंदी की पत्थर की प्रतिमा तथा भगवान कार्तिकेय (षणमुख) की दुर्लभ पाषाण प्रतिमा शामिल हैं। ये सभी कलाकृतियां तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों से संबंधित हैं और चोल तथा विजयनगर-नायक काल की उत्कृष्ट शिल्पकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार इन प्राचीन धरोहरों की वापसी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

'ग्रो मोर,अवीव मोर' के मंत्र के साथ विकसित भारत की ओर बढ़ रहा देश : मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी का भारत ग्रो मोर,अवीव मोर के मंत्र के साथ विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अब चंद्रयान की सफलता तक सीमित नहीं है बल्कि गगनयान मिशन और अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लक्ष्य पर भी काम कर रहा है। मेलबर्न में आयोजित भव्य प्रवासी भारतीय समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।

यूजीसी-नेट समाजशास्त्र पेपर लीक के आरोपों पर शिक्षा मंत्रालय सख्त,जांच का निर्देश दिया

नई दिल्ली,09 जुलाई 2026। देश की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नीट-यूजी परीक्षा के विवाद के कुछ ही सप्ताह बाद, अब यूजीसी-नेट जून 2026 की समाजशास्त्र परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों के अनुसार, परीक्षा से पहले 100 पन्नों की एक पीडीएफ फाइल वायरल हुई थी, जिसमें मौजूद करीब 90 प्रश्न वास्तविक प्रश्नपत्र से हुबहू मेल खाते हैं। इस खुलासे ने लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ा दी है। शिक्षा मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं, हालांकि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

2.25 लाख रुपये में पेपर का सौदा और गिरोह का दावा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,यह कथित प्रश्नपत्र बिहार,उत्तर प्रदेश,हरियाणा,दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में सक्रिय एक संगठित गिरोह द्वारा 2.25 लाख रुपये में बेचा जा रहा था। यह दावा परीक्षा प्रणाली में सेंधमारी के गहरे नेटवर्क की ओर इशारा करता है। सूत्रों का कहना है कि शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस बीच, परीक्षा से जुड़ी सुरक्षा और गोपनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि यदि इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न पहले से ही लीक हो गए थे,तो परीक्षा की निष्पक्षता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। यह मामला ऐसे समय पर आया है जब देश नीट-यूजी परीक्षा के विवाद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट परीक्षा को रद्द करना पड़ा था,जिसके बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई और कई गिरफ्तारियां भी हुईं। पुनः आयोजित नीट-यूजी परीक्षा, जो 21 जून को संपन्न हुई।

राहुल गांधी का हमला : सरकार विश्वसनीयता बनाए रखने में पूरी तरह विफल...

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक रिपोर्ट साझा करते हुए आरोप लगाया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के गोपनीय डेटाबेस से जुड़ी 100 पन्नों की पीडीएफ परीक्षा से पहले ही लीक हो गई थी। राहुल गांधी ने दावा किया कि यही गिरोह आगामी CSIR-NET, HTET और ADA जैसी परीक्षाओं के पेपर भी लीक करने का दावा कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लाखों छात्रों की मेहनत का सम्मान करने में विफल रही है। राहुल गांधी के अनुसार,बार-बार पेपर लीक की घटनाओं से यह स्पष्ट है कि परीक्षा प्रणाली का तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। उन्होंने छात्रों से एकजुट होकर बदलाव के लिए आवाज उठाने का आह्वान किया है।

कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा...लॉरी से टकराई कार,7 लोगों की मौत,दो गंभीर

बेंगलुरु,09 जुलाई 2026। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में गुरुवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर येल्लापुर थाना क्षेत्र के अराबैल घाट स्थित बालागारा क्रॉस के पास रात करीब 1:30 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार, धारवाड़ से धर्मस्थल और चिकमगलूर की यात्रा पर जा रही एक एमयूवी (मल्टी यूटिलिटी व्हीकल) की सामने से आ रही लॉरी से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे के समय वाहन में चालक समेत नौ लोग सवार थे। घायल दोनों लोगों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हुबली के केआईएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। उनका उपचार जारी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने बताया कि चालक संजीव कथित तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चला रहा था। इसी दौरान वाहन सड़क की दाईं ओर चला गया और अंकोला की ओर से आ रही लॉरी से आमने-सामने टकरा गया। पुलिस के अनुसार, चालक एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ पार्ट-टाइम डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के रूप में भी काम करता था। मृतकों की पहचान चालक संजय अंगड़ी (33), बसवराज (48), अभिषेक ईश्वर (28), अक्षय (26), अभिषेक (26), मंजूनाथ चुलाकी (32) तथा एक अन्य व्यक्ति के रूप में हुई है। सभी मृतक धारवाड़ के निवासी थे और धार्मिक यात्रा पर निकले थे। सातवें मृतक की पहचान की प्रक्रिया जारी है। घायल शिवराज की शिकायत के आधार पर येल्लापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 (तेज या लापरवाही से वाहन चलाना), 125(2) (दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना) और 106(1) (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

तृणमूल के तीन पूर्व राज्यसभा सदस्य भाजपा में शामिल

कोलकाता,09 जुलाई 2026। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के तीन पूर्व राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सॉल्टलेक स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य की उपस्थिति में तीनों नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। तीनों नेता पूर्व में तृणमूल कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के सदस्य रहे थे। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चा चल रही थी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और पश्चिम बंगाल के विकास में विश्वास व्यक्त करते हुए तीनों नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि अब सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक की पहचान केवल भाजपा कार्यकर्ता के रूप में होगी।

लग्जरी जेट-हेलिकॉप्टर में घिरीं ममता की पार्टी

ईडी की जांच में बड़ा खुलासा...पार्टी फंड से खरीदे गए हेलीकॉप्टर और लग्जरी जेट

नई दिल्ली,09 जुलाई 2026। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने पार्टी के तीन बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है,जिनमें करीब 440 करोड़ रुपये जमा बताए गए हैं। ईडी का दावा है कि जांच के दौरान ऐसे वित्तीय लेनदेन सामने आए हैं, जिनसे यह संदेह पैदा हुआ है कि पार्टी के पैसों से एक लग्जरी बिजनेस जेट और एक वीआईपी हेलिकॉप्टर खरीदा गया,लेकिन बाद में उन्हीं विमानों को किराए पर लेकर इस्तेमाल किया गया। यह पहली बार है जब ईडी किसी राजनीतिक दल की फंडिंग की स्वतंत्र रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के अकाउंट की जांच दिल्ली आबकारी नीति मामले के तहत की गई थी।यह पूरा मामला कोलकाता स्थित एविएशन मैनेजमेंट और लीजिंग कंपनी Carewell Aviation India Pvt Ltd पर ईडी की छापेमारी के बाद सामने आया। एजेंसी के मुताबिक, यह कंपनी सितंबर 2021 में बनाई गई थी। इसी साल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी थी। ईडी के अनुसार, अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के बैंक खातों से करीब 160 करोड़ रुपये केयरवेल एविएशन को ट्रांसफर किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने इनमें से 82.96 करोड़ रुपये एक अन्य नई कंपनी को भेज दिए। ईडी का आरोप है कि टीएमसी से मिले पैसों का इस्तेमाल कर केयरवेल एविएशन ने करीब 112 करोड़ रुपये की लागत से एक Embraer Legacy 600 बिजनेस जेट और एक Agusta 109 SP हेलिकॉप्टर खरीदा। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2023 में हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए केमैन आइलैंड्स स्थित एक कंपनी से लगभग 16 करोड़ रुपये (करीब 17 लाख अमेरिकी डॉलर) का असुरक्षित कर्ज लिया गया था। केमैन आइलैंड्स दुनिया भर में ऑफशोर कंपनियों के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। एजेंसी अब इस विदेशी फंडिंग के सोर्स और उद्देश्य की भी जांच कर रही है। ईडी की जांच का सबसे अहम पहलू यही है कि जिन विमानों को कथित तौर पर टीएमसी के फंड से खरीदा गया, बाद में वही विमान पार्टी को किराए पर दिए गए। एजेंसी का कहना है कि विमान खरीदने के बाद केयरवेल एविएशन ने उन्हें टीएमसी को चार्टर सेवा के रूप में उपलब्ध कराया और विमान इस्तेमाल करने के नाम पर पार्टी से लगातार भुगतान लिया गया। सरल शब्दों में समझें तो यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति अपने ही पैसे से कार खरीदे, लेकिन बाद में उसी कार का इस्तेमाल करने के लिए हर बार किराया भी देता रहे। ईडी को शक है कि यह पूरा सिस्टम असली लेनदेन को छिपाने और पार्टी के फंड को दूसरी जगह ट्रांसफर करनेके उद्देश्य से बनाई गया हो सकता है।

एक ही परिवार के 4 लोगों ने खाया जहर,पिता-बेटी की मौत

पटियाला,09 जुलाई 2026। पंजाब के पटियाला शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। यहां एक ही परिवार के चार सदस्यों ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना के बाद परिवार के सभी सदस्यों की हालत बिगड़ गई,जिसके बाद उन्हें तत्काल इलाज के लिए सरकारी राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान परिवार के मुखिया और उनकी 13 वर्षीय बेटी की मौत हो गई,जबकि मां और बेटा जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। एक हंसता-खेलता परिवार अचानक इस तरह के संकट में घिर गया, जिससे पूरे इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

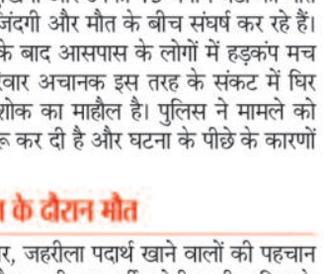

पिता और बेटी की इलाज के दौरान मौत

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, जहरीला पदार्थ खाने वालों की पहचान 45 वर्षीय विकास बातिश और उनकी 13 वर्षीय बेटी खुशी बातिश के रूप में हुई है। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। वहीं,परिवार की 43 वर्षीय महिला तमन्ना बातिश और उनके 11 वर्षीय बेटे कनव का इलाज अभी भी राजिंदरा अस्पताल में जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। मेडिकल टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर...

एक ही परिवार के चार लोगों द्वारा जहरीला पदार्थ खाने की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामले से जुड़े सभी पहलुओं को खंगालना शुरू कर दिया है। डीएसपी सिटी-1 संजीव सिंगला ने बताया कि प्रारंभिक जांच में परिवार से जुड़े घरेलू लेन-देन और आर्थिक विवाद की बात सामने आई है। आशंका जताई जा रही है कि आर्थिक तनाव के चलते परिवार ने यह खौफनाक कदम उठाया होगा।

मेरठ ललिता गौतम हत्याकांड पर बवाल...न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे दलित संगठन

मेरठ,09 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 20 वर्षीय दलित छात्रा ललिता गौतम की निर्मम हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद से ही मेरठ में आक्रोश का माहौल है और न्याय की मांग को लेकर जातिगत विरोध-प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं, दलित संगठनों ने एकजुट होकर छात्रा को न्याय दिलाने के लिए एक 'दलित महापंचायत' का आयोजन किया है। संगठनों की स्पष्ट मांग है कि इस हत्याकांड के सभी दोषियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और दोषियों को फांसी की सजा मिले। इसके साथ ही पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग उठाई गई है।

क्या है मेरठ का ललिता गौतम हत्याकांड? मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र के गगन एंक्लेव में रहने वाली 20 वर्षीय ललिता गौतम बीए की छात्रा थी। 15 मई का दिन उनके परिवार के लिए काल बनकर आया। ललिता अपनी परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन जब देर शाम तक वह वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। कोई सुराग न मिलने पर टीपी नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें ललिता को कल्याणपुर गांव निवासी अंकुश नामक युवक के साथ देखा गया। इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने अंकुश को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें उसने ललिता की हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अंकुश और ललिता के बीच प्रेम संबंध थे। घटना वाले दिन जब दोनों साथ थे, उसी दौरान अंकुश ने ललिता के मोबाइल फोन में कुछ फोटो और चैट देखीं। पुलिस के मुताबिक, आरोपी को शक हो गया कि ललिता के किसी अन्य युवक से भी संबंध हैं। इसी शक और आक्रोश में आकर उसने ललिता की हत्या कर दी और शव को मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र के उपसिया जंगल स्थित गन्ने के खेत में ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने बाद में उसी स्थान से छात्रा का शव बरामद किया।

अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा,13 जुलाई को संभावित सुनवाई

अयोध्या,09 जुलाई 2026। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चंदे की कथित चोरी का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज पर है। इस संवेदनशील प्रकरण की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मामले को सीबीआई को सौंपने और एक विशेष जांच दल के गठन की मांग की गई है। इससे पहले,29 जून को सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए कहा था कि गर्मी की छुट्टियों के बाद इसे नियमित बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। 13 जुलाई से अदालत की नियमित कार्रवाई फिर से शुरू हो रही है, ऐसे में याचिका के स्टेटस से संकेत मिल रहे हैं कि इस पर सुनवाई उसी दिन हो सकती है। हालांकि, अंतिम सूची आने तक इस पर संशय बना हुआ है। इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट ने मंदिर प्रशासन के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार की कई परतें खोल दी हैं। रिपोर्ट में 30 वर्षीय अविनाश शुक्ला को इस पूरी साजिश का मुख्य सूत्रधार बताया गया है। जांचकर्ताओं के अनुसार, मंदिर के दान गणना कक्ष में लगभग 40 दिनों के भीतर दान राशि की चोरी की 70 घटनाएं सामने आई हैं। विशेष जांच टीम का मानना है कि पूरा चोरी का नेटवर्क अविनाश शुक्ला के इर्द-गिर्द ही घूम रहा था। उसकी गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ही पांच अन्य संदिग्ध आरोपियों की पहचान संभव हो सकी और जांच टीम उस तरीके को समझ पाई,जिसका इस्तेमाल दान राशि में हेराफेरी करने के लिए किया जाता था। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है, जो आरोपी के भ्रष्टाचार को और स्पष्ट करता है। 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' द्वारा दान राशि की गिनती के लिए नियुक्त कर्मचारियों को मासिक वेतन के रूप में 15 हजार रुपये से कुछ अधिक राशि ही मिलती है।

बाढ़ के पानी में बह गए 3000 एलपीजी गैस सिलेंडर,वायरल वीडियो ने बढ़ाई चिंता

महाराष्ट्र,09 जुलाई 2026। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस दौरान पनवेल तालुका के चावणे स्थित एचपीसीएल के पातालगंगा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में जलभराव के कारण एक हैरान कर देने वाली घटना घटी है। अत्यधिक बारिश और बाढ़ के पानी के दबाव के कारण प्लांट परिसर में रखे करीब 3 हजार एलपीजी गैस सिलेंडर बहकर पास की पातालगंगा नदी में पहुंच गए। सोशल मीडिया पर नदी में तैरते इन सिलेंडरों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने स्थानीय प्रशासन और आम जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा है कि इन सिलेंडरों में से कुछ पूरी तरह भरे हुए हैं, जबकि कुछ खाली हैं। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए रायगढ़ जिला प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी किशन जावले ने नागरिकों के लिए एक आपातकालीन एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि नदी या उसके किनारों पर बहकर आए किसी भी गैस सिलेंडर के पास न जाएं और न ही उन्हें उठाने या घर ले जाने की कोशिश करें। उन्होंने बताया कि यह फिलहाल अज्ञात है कि किन सिलेंडरों में गैस भरी है और उनकी स्थिति क्या है।

संपादकीय

सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता का सवाल

देश की शिक्षा इस समय हर स्तर पर दो खंडों में बंट गई है, सरकारी और निजी। सरकार के पास संसाधन नहीं हैं,अतः उसे शिक्षा में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना ही है। समाज के जिस वर्ग को शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है,वह सरकारी स्कूलों पर निर्भर है। इसको वह अपनी मजबूरी में ही स्वीकार कर रहा है,क्योंकि इसकी गुणवत्ता और साख आज सवालों के घेरे में है। सरकारी तंत्र में नियमित सेवा में नियुक्त और हर साधन संपन्न व्यक्ति अपने बच्चों को सामान्य सरकारी स्कूलों के बजाय निजी स्कूलों में भेजना पसंद कर रहा है। यहां दो वर्ग बन गए हैं।

सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रतिस्पर्धा इतनी कठिन हो चुकी है कि उसके लिए कोचिंग संस्थानों में जाना जरूरी है। कोचिंग एक शुद्ध व्यापार है। यहां जिन परिस्थितियों में संवेदनशील आयु के युवा आते हैं,रहते और पढ़ते हैं, वे अस्वीकार्य स्तर का तनाव, चिंता और घबराहट उत्पन्न करती हैं। कक्षा 11-12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी होती है। यदि उन्हें न्यूनतम अंक नहीं मिलें तो आगे की प्रतियोगी परीक्षा में बैठ नहीं सकेंगे। फिर उन्हें मेडिकल,इंजीनियरिंग या अन्य व्यावसायिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी,कोचिंग में भागीदारी और वहां लगभग प्रतिदिन प्रतिस्पर्धा में आगे रहने का दायित्व उठाना पड़ता है। इस सबके साथ उन पर माता-पिता की अपेक्षाओं और आशाओं का लगातार बढ़ता दबाव भी है।

दूसरी ओर समाज में नैतिकता के प्रति लगातार बढ़ रही शिथिलता और व्यवस्था में कर्तव्यनिष्ठा की कमी ने पेपर-लीक का ऐसा जाल रच दिया है, जिसका कोई समाधान सामने नहीं आ रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कुछ नकल और पर्चा-लीक में भागीदार माफिया दशकों से इसमें संलग्न हैं और सरकारी तंत्र तथा न्याय व्यवस्था की खिल्ली उड़ा रहे हैं। किसी को भी विश्वास नहीं है कि भविष्य में सरकारी व्यवस्था नियमों का पालन करवा सकेगी। साठगांठ इतनी सशक्त है कि उसे तोड़ पाना सामान्य व्यक्ति को असंभव लगता है। नकल माफिया,साल्वर गैंग, पर्चा-लीक इत्यादि सभी शिक्षित लोगों द्वारा ही चलाए और निर्देशित किए जाते हैं। इन समस्याओं का त्वरित समाधान खोजना आवश्यक है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की साख पुनः स्थापित करने के लिए दीर्घकालीन उपाय खोजने होंगे। यह तभी संभव है जब उन परिस्थितियों को ईमानदारी से विश्लेषित किया जाए, जिसके कारण कर्तव्यनिष्ठा में गिरावट आई और नैतिकता केवल पुस्तकों में सिमट कर रह गई।

संविधान निर्माताओं ने 14 वर्ष तक के हर बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने के निर्देश दिए थे। यदि प्रारंभ से ही सभी सरकारों ने इस जिम्मेदारी को निभाया होता,सभी बच्चों को शिक्षा का एक समान अवसर देने की भावना को व्यावहारिक स्वरूप दिया होता,अपना उत्तरदायित्व स्वीकारा होता और उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए होते, हर वर्ग और आर्थिक स्थिति के बच्चे एक स्कूल में और साथ-साथ पढ़ते तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। सरकारें यदि ऐसा करतीं तो समाज स्वयं आगे आता। संसाधनों की कमी कुछ वर्षों में स्वतः ही समाप्त हो जाती। सरकारी स्कूलों के प्रति घोर लापरवाही,उसके अध्यापकों से हर प्रकार का गैर-शैक्षिक कार्य करवाना,नियमित नियुक्तियां न करना कुछ ऐसे अक्षम्य निर्णय रहे हैं,जिनके प्रभाव को कम करना और रोकना आवश्यक है। हालांकि शिक्षा नीति-2020 के बाद एक आशाजनक स्थिति बनी है कि भारतीय संस्कृति के आलोक में नीति निर्माण हुआ है और इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व को स्वीकारा गया है। ये अत्यंत संवेदनशील कार्यक्षेत्र हैं, इनको उचित महत्व दिए बिना शिक्षा में वास्तविक समानता की ओर बढ़ना कठिन होगा। शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के छह प्रतिशत खर्च करने की कोठारी आयोग (1964-66) की सिफारिश को गंभीरता से अपनाना होगा।

सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की नियमित नियुक्ति को पीछे धकेलना शिक्षा की गुणवत्ता के लिए आत्मघाती रहा है। थोड़े से मानदेय पर सरकारी स्कूलों में अध्यापक नियुक्त करना,विश्वविद्यालयों में अतिथि-अध्यापक,लेक्चर आधारित मानदेय जैसे प्रयोग शिक्षा में गुणवत्ता,शोध की उत्कृष्टता और अध्यापकों के उत्साह तथा लगनशीलता को लील गए। सरकारें अब तय करें कि केवल नियमित अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। तीन महीने के लिए स्थानीय स्तर पर सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाएं लेने का अधिकार प्राचार्य को देना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर यह अधिकार कुलगुरुओं को होना चाहिए।

रूक,ठहर ओ हेकड़ मनुष्य वर्ना मिट्टी में मिला दिया जाएगा

आत्माराम यादव
लखनऊ,उत्तरप्रदेश

पृथ्वी संकट में है। मानव इतिहास में इस पृथ्वी पर अब तक लाखो युद्ध लड़े जा चुके है ओर 200 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जा चुके है। मरने वालों में जन्म लिए बच्चे से लेकर 100 साल तक के लोगों मे गर्भवती माताए भी शामिल रही है जो अपने गर्भ में पल रहे नवजात को दुनिया में जन्म दिये बिना मौत की शिकार हुई है। किन्तु जो दायित्वाधीन है वे मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन-बैठक तक ही सीमित रहते हुए वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच तक सिमटकर रह गए है। आज तक किसी भी राष्ट्र या राष्ट्राध्यक्ष की असफल नीति या संवैधानिक व्यवस्था के दोषी रहकर क्रूर शासक होने के मामले में दोषी पाये जाने पर इस मंच ने कोई कार्यवाही की हो ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है,आप कुल मिलाकर इस संगठन को पिंजरे में कैद तोता भर से ज्यादा तुलना नहीं कर सकते हो। पृथ्वी अपने आँचल में सभी प्राणियों-जीवों ओर वनस्पति सहित धातुओं को जन्म देकर उन्हे उपहार में देती रही है किन्तु इन्हे बलात लूटने वाले शक्तिशाली राष्ट्रों के प्रमुख अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए पृथ्वी के छोटे सम्पन्न देशों पर कब्जा करने के लिए युद्ध कर रहे है। अब तक के शत प्रतिशत युद्ध मानवाधिकारों के लिए नही हुये बल्कि उन देशों के भूभाग को हड़पने, संसाधनों-खनिज संपदाओं को लूटने-कब्जा कर बलात डकैती डाल कर कब्जाने के लिए हो रहे है।

अमेरिका ताकतवर है ओर उसकी मुद्रा डालर पूरी दुनिया पर कब्जा करे इसलिए उसे दुनिया का चौधरी बनने का भूतसवार है,भले वह युद्ध में मुंह की खाकर भी बेशर्मी से छोटे देशों को परमाणु नीति-कार्यक्रमों की शक्ति संपन्नता न होने की दुहाई देकर निगलने को तैयार है। जैसे बड़ी मछ्ली छोटी को निगल जाती है वैसे ही अमेरिका ईरान के मामले में ओर रूस यूक्रेन के मामले में बड़ी मछ्ली बने हुए है, पर वे बड़ी मछ्ली नहीं बन सके। अमेरिका रूस यूक्रेन आदि देशों की महत्वाकांक्षाओं से थोपे गए युद्ध 8 महीने से 3 की अवधि पूरा करने के बाद किसी परिणाम पर नहीं पहुंचे जबकि इन युद्धों के महाविनाश से रूस के 14 लाख सैनिक तथा यूक्रेन के 5,25,000 से 6,25,000 सैनिक हताहत हुए हैं,जिनमें लगभग 1,25,000 से 1,50,000 सैनिकों की मौत का अनुमान है। दूसरी ओर अमेरिका और इजरायल की सेनाओं ने 28 फरवरी को ईरान पर युद्ध शुरू किया, जिसमें ईरान में 3,468 लोग, लेबनान में 3,371 लोग 376 बच्चे और 496 महिलाएं शामिल हैं असमय बेमौत मारे गए हैं,यह मिसाइल आदि के हमले से होने वाले रक्तपात,इन चौधरियों की हठधर्मिता है जिसने मानवता के विनाश के साथ पृथ्वी-सागर और ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा रखी है।

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

अमेरिका दुनिया का चौधरी बनने के लिए बेबजह अनेक देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर उन देशों को गुलाम बनाने के लिए पागल बना हुआ है। यूरोपीय देशों में यूक्रेन, चीन,रूस,इज़राइल,ईरान जैसे देशों में विगत 3 सालों से चल रहे युद्ध में हजारों भव्य इमारतों का विनाश हुआ है, उन देशों के नागरिकों की असमय मृत्यु इस पृथ्वी के लिए संकटापन्न है जिसमें एक मकान-एक भवन खड़ा करने के लिए पृथ्वी के दर्जनों वृक्ष उसके खिड़की दरवाजे के रूप में अपनी आहुति देते है। शहर के शहर नष्ट होना यानि एक शहर में एक लाख से 20 करोड़ तक की आबादी के हिसाब से बहुमंजिला भवनो के निर्माण में पृथ्वी के कितने बड़े हिस्से के पेड़-पौधों ने अपने आप को मिटाया होगा तब यह विकास देखने को मिल रहा हैं जो पलक झपकते ही युद्ध में एक राकेट- मिसाइल,ड्रोन लेजर किरणों आदि अत्याधुनिक शस्त्र से मनुष्य सभ्यता को समाप्त करने पर आमादा है। एक प्रश्न युद्ध पीड़ित हर व्यक्ति के मन में कोंधता है की आखिर सयुंक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग अपंग लाचार क्यों है? क्या वह युद्ध पीड़ित के स्थान पर उस राष्ट्राध्यक्ष के घर परिवार को रखकर अपनी बात कह सकता है जिस देश-राष्ट्र के नागरिक-उसके परिवार के मरने-बिछुड़ने या आजीवन अपंग होने के दर्द को वह राष्ट्राध्यक्ष क्या जाने जो युद्ध में इन परिवार का कीमा बना रहा है,इस पीड़ा को जानने के लिए ट्रम्प जैसे नराधम राष्ट्राध्यक्ष को मानवीय होने के गुण को समझना होगा ओर अनुभव करना होगा कि यह दर्द-अपने या दूसरे देश के किसी भी निर्दोष नागरिक के सारे मानवीय पहलू ओर आत्मीय समवेदनाओं के प्रति मानवीयता कि सारी सीमाओ को पार कर चुके है। यदि पैसे के बल पर कोई चौधरी बने तो वह चौधराहट ज्यादा दिन कि नही होती ओर ऐसी उपलब्धि कोई बहदुरी नही बुझदिली से ज्यादा कुछ नही होती जिसे समय नकार देता है। ट्रम्प दुनिया का ऐसा ही चौधरी बना है जिसे इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा ओर उसके देश अमेरिका की आने वाली पीढ़ी शर्मसार होकर आज की पीढ़ी को क्षमा नहीं करेगी।

सच तो यह है कि न पृथ्वी गुलाम है और न ही प्रकृति गुलाम है। प्रकृति सहनशील है। मगर उसकी भी एक सीमा है। प्रकृति के साथ लगातार की जाने वाली छेड़छाड़ के बावजूद प्रकृति सहनशीलता के साथ अपने ऑचल में इस मनुष्य को पाल रही है। हॉ, प्रकृति नाराज है ट्रम्प,पुतिन ओर शी जिनपिंग जैसे मनुष्य की बदतमीजियों से, इसलिये वह आजकल भूस्खलन द्वारा हिमालय को झुकाने के लिए बादल फटने के साथ पहाड़ों के दरकने-खिसकने का सबक देकर मानवीय आपदा कि घोषणा कर रही है कि उसके द्वारा जो अनियोजित निर्माण कर पहाड़ों कि कटाई-छ्टाई कि जा रही है,उसे दुनिया का वायुमंडल वापसी में पृथ्वी पर भूस्खलन,बादल फटने से तबाही, भूकंप जैसे अनेक उपद्रवों का रौद्र रूप दिखाकर मनुष्य की हेकड़ी निकालकर उसे मिट्टी में मिलाने को तत्पर हुई है। अंततोगत्वा विश्व भर में कहीं भूकंप आ रहे है,कहीं सूखा पड़ रहा है।

मनुष्यों की यह मौजूदा सभ्यता नहीं जानती कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वालों की प्रकृति कभी माफ नहीं करती है। यह धरती बहुत सहनशील है मगर जब इसकी सहनशीलता को चुनौती दी जाती है तो फिर प्रकृति बदला लेती है। जब प्रकृति बदला लेती है तो अपने आपको ईश्वर से भी ऊपर समझने वाले इस मनुष्य को भूकंप के मार्फत कई फुट नीचे गाड़ देती है। इस धरती के नीचे कई सभ्यतायें गड़ी हुई है। वे सभ्यतायें जिन्हें अपने आप पर गर्व था,मौजूदा मनुष्य सभ्यता की ही तरह बड़ा भारी गुमान, हेकड़ी और घमण्ड रहा होगा,प्रकृति के नियमों को बदलने और पर्यावरण को प्रदूषित करने की मनुष्य की इस हिमाकत को आप यूं भी कह सकते है कि जब धरती पर पाप बढ़ने लगते है तब वह प्रकृति उस मनुष्य जाति के अध्याय को इतिश्री करके इसे अपने आप में समेट लेती है। मौजूदा मनुष्य जाति इस समय यह सब कर रही है लेकिन यह सब अधिक दिन तक नहीं चलने वाला है। इस प्रकृति से ऊपर कुछ भी नहीं है । यह बित्ता सा मनुष्य इस हेकड़ी में है कि यह प्रकृति की धारा को उल्टा चला सकता है। चाँद पर रॉकेट में बैठकर मनुष्य को भेजकर या मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजकर वहां की तस्वीरें लेने से मनुष्य अभी प्रकृति से बड़ा नहीं हो गया है। याद रखना होगा कि जब प्रकृति को क्रोध आता है और वह मनुष्य जाति से बदला लेती है तो पहले तो वह चेतावनी देती है मनुष्य को कि वह अपने आप को ईश्वर समझने के नापाक इरादों से बाज आ जाये। फिर भी जब मनुष्य नहीं समझता तो वह उसे अपने सर्वशक्तिमान होने के कुछ नमूने दिखाती है। मगर इसके बावजूद मनुष्य को अक्ल नहीं आती है तो फिर यह प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। नतीजतन ज्वालामुखी फटता है, महामारी फैलती है, भूकम्प आते है और फिर एक दिन विशाल समुद्र इस छोटी सी धरती पर बसी मनुष्य जाति को लील जाता है।

मौजूदा मनुष्य जाति का भी एक दिन यही हश्र होना है। मौजूदा सभ्यता का प्रतिनिधि यह मनुष्य लगातार पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहा है। मनुष्य मनुष्य को जीतने के लिये रोज परमाणु बम बना रहा है और इसके परीक्षण वह कभी धरती के भीतर करता है तो कभी समुद्र के भीतर पूरे वातावरण को इस मनुष्य ने जहरीली गैसों व बारूद के जहरीले धुएं से ऐसा प्रदूषित कर दिया है कि वह खुद आज एक सॉस ताजा हवा के लिये तरस रहा है। मनुष्य की इस हरकत से स्वयं मनुष्य जाति ही नहीं,पशु-पक्षी,वनस्पति,क्रीट-पतंगे तक परेशान है, जिन झूमते पेड़ों के गीत और लोगी सुनकर आकाश में मेघ गेहरा कर बरसने के लिए आया करते थे, उन पेड़ों की मनुष्य ने इस बेरहमी से कटाई की कि हरियाली धरती का हरा रंग ही जैसे पोछ दिया गया और धरती को बंजर बना दिया गया। धरती पर कटते पेड़ों को बचाने के लिये सरकार ने नई-नई योजनाएं बनाई और इन कागजी योजनाओं के धुर्रे बिखरने के लिये लकड़ी चोर माफिया भी उसी मुस्तैदी से सक्रिय हो गये भारत की आबादी जिस तेजी से बड़ी उस रफतार से पेड़ नहीं लगाये गये। धरती उतना ही देती है जितनी उसकी प्राकृतिक क्षमता है,मगर मनुष्य ने धरती की उर्वरता बढ़ाने के लिए रसायनों का प्रयोग किया और उसकी कृत्रिम उर्वरता को बढ़ाने के अप्राकृतिक उपाय किये। नतीजा यह हुआ कि धरती की प्राकृतिक खुशबू तक गायब होती जा रही है। मनुष्य अपनी आबादी पर नियंत्रण लगाता मगर मनुष्य ने यह नहीं किया। कम से कम भारत में तो आज भी अधिक बच्चे पैदा करने की होड़ मची है नाले किनारे झुग्गी-बस्तियों में कुत्ते बिल्ली जैसे बच्चे पैदा होते है जो धरती पर बोझ की तरह है। इन बच्चे पैदा करने वालों से पूछो तो वे कहते है-ईश्वर ने पैदा किये-ये फालतू लोगों के तर्क है

अब मानसून ने भी समय पर आना छोड़ दिया है जब मानसून के आने की भविष्यवाणी की जाती है तब मानसून फटकता भी नहीं है। मानसून की भविष्यवाणी करने वाले मौसम वैज्ञानिकों की बात पर अब भरोसा नहीं करते,उल्टे मजाक उड़ाते है। नई सदी शुरू होने के साथ ही मौसम में कई बदलाव भी देखे गये है। अब धरती आग के गोले की तरह धधकती है यह स्थिति केवल भारत ही नहीं दुनिया के अधिकतर देशों की है जहां धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से हिमखण्ड तक पिघलने लगे है जिससे पर्यावरण को भारी क्षति पहुँच रही है। मौसम के निरंतर गरम होते मिजाज की वजह से दुनिया में औसतन तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। भारत में सतह का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तथा समुद्र का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इसलिये अब सर्दियाँ देर से आती है। गर्मी भीषण गर्मी में बदल रही है इससे या तो वर्षा होती ही नहीं होती है तो नियत समय पर न होकर कभी भी होती है और अधिक होती है। विश्व के पर्यावरणविद् इसके लिये कई तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे है। ग्लोबल वार्मिंग,ग्रीन हाउस एमीसन, ओजोन की परत आदि पर इस बात पर कोई सलाह नहीं दे रहा है कि अब यदि इस पृथ्वी को बचाना है तो मनुष्य प्रकृति के साथ चलने, उससे छेड़छाड़ बंद कर दे। परमाणु हथियारों के जखीरे,हथियार गोले बारूद के बेतहाशा निमार्ण को बंद करें व उनके उपयोग भी बंद करे, युद्ध की जगह शांति से जीना सीखे व पूरी पृथ्वी पर हरियाली की परत बिछा दे। पृथ्वी को केमिकल मुक्ति कर उसे प्राकृत अवस्था में उर्वरित होने का अवसर दे। आबादी पर रोक लगाये ताकि प्रकृति के संसाधनों की हिस्सेदारी में लूट मार न मचे। वर्ना वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी।

बांकीपुर उपचुनाव : भाजपा के अभेद्य किले में प्रशांत किशोर की अग्निपरीक्षा

अजय कुमार
लखनऊ,उत्तरप्रदेश

बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधान सभा उपचुनाव अब केवल एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है। यह मुकाबला तीन बड़े राजनीतिक संदेशों की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ भाजपा अपने तीन दशक पुराने गढ़ को बचाने की चुनौती से जूझ रही है,दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल अपने परंपरागत वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश में है, जबकि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव मैदान में उतरकर अपनी पूरी राजनीतिक विश्वस नीयता दांव पर लगा चुके हैं। यही वजह है कि राजधानी पटना की यह सीट पूरे बिहार की सबसे चर्चित चुनावी रणभूमि बन गई है। हालिया घटनाक्रम ने मुकाबले को और रोचक बना दिया है। जन सुराज के वरिष्ठ नेता रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह ने पार्टी छोड़कर एनडीए प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार तो हो सकते हैं,लेकिन राजनीतिक दल चलाने की क्षमता उनमें नहीं दिखती। इसी बीच प्रशांत किशोर ने अपने नामांकन कार्यक्रम में भी बदलाव करते हुए अब 13 जुलाई को नामांकन करने का फैसला किया है। पार्टी अध्यक्ष मनोज भारती ने कार्यकर्ताओं के लिए नया सर्कुलर जारी कर पूरी ताकत के साथ नामांकन कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया है। दूसरी ओर राजद ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया,लेकिन उम्मीदवार घोषित होने के साथ ही पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा। पहले सांसद सुरेंद्र यादव ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह रेखा गुप्ता को नहीं जानते, फिर वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने भी उम्मीदवार चयन पर सवाल उठा दिए। इतना ही नहीं,तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने वीणा मानवी को मैदान में उतारकर महागठबंधन के वोटों में संभावित सेंध का संकेत दे दिया। कांग्रेस भी उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया से असहज दिखाई दे रही है। इन घटनाओं ने विपक्षी एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बांकीपुर का चुनावी इतिहास भाजपा के पक्ष में बेहद मजबूत रहा है। वर्तमान स्वरूप में 2010 के परिसीमन के बाद से यह सीट लगातार भाजपा के पास रही है,जबकि यदि पुराने पटना पश्चिम क्षेत्र को जोड़ दिया जाए तो 1995 से यहां भाजपा का दबदबा कायम है। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा चार बार और उनके पुत्र नितिन नवीन लगातार पांच बार विधायक रहे। 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नितिन नवीन को 98,299 वोट मिले थे, जबकि राजद की रेखा गुप्ता को लगभग 46 हजार और जन सुराज की उम्मीदवार वंदना कुमारी को केवल 7,717 वोट मिले थे। यानी भाजपा और जन सुराज के बीच करीब 90 हजार वोटों का अंतर था। यही आंकड़ा बताता है कि प्रशांत किशोर के सामने चुनौती कितनी कठिन है। फिर भी प्रशांत किशोर ने सुरक्षित सीट चुनने के बजाय भाजपा के सबसे मजबूत किले में उतरने का फैसला किया। उनका तर्क है कि यह चुनाव केवल जीत-हार का नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा बदलने का प्रयास है। चुनावी रणनीतिकार के रूप में नरेंद्र मोदी से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब पहली बार खुद जनता से वोट मांग रहे हैं। पिछले कई महीनों से उन्होंने बांकीपुर में अलग तरह का चुनाव अभियान तैयार किया है। सुबह पार्कों में युवा टीम लोगों से संवाद करती है,दिन में महिला कार्यकर्ता घर-घर पहुंचकर महंगाई, शिक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाती हैं,जबकि शाम को नुक्कड़ सभाओं,चौपाल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भाजपा और राजद दोनों पर हमला बोला जाता है। सोशल मीडिया से लेकर मोहल्ला स्तर तक जन सुराज ने हाईटेक और जमीनी प्रचार का मिश्रित मॉडल तैयार किया है। लेकिन चुनाव केवल अभियान से नहीं जीते जाते। बांकीपुर का सामाजिक समीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग चार लाख मतदाता हैं। इनमें कायस्थ मतदाता निर्णायक माने जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 14 प्रतिशत बताई जाती है। भाजपा ने इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा वैश्य, सवर्ण, शहरी मध्यम वर्ग और भाजपा का पारंपरिक संगठनात्मक नेटवर्क भी इस सीट पर मजबूत माना जाता है। दूसरी ओर मुस्लिम मतदाता लगभग 8 से 10 प्रतिशत माने जाते हैं और उनका बड़ा हिस्सा भाजपा विरोधी मतदान करता रहा है। ऐसे में यदि विपक्ष बंटता है तो मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा राजद की ओर जाने की संभावना अधिक मानी जा रही है, क्योंकि राजद लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाजपा को वास्तविक चुनौती वही दे सकता है। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी उम्मीद युवा मतदाता हैं।

हिंद-प्रशांत में भारत का बता सामर्थ्य एवं साझेदारियां

डॉ. ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

भारत आज केवल विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति ही नहीं, बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति के रूप में अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने जिस आत्मविश्वास,स्पष्टता और दूरदृष्टि का परिचय दिया है, उसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल दी है। कभी जो भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशी हथियारों पर निर्भर था,वही भारत आज आधुनिक मिसाइलों, रक्षा प्रणालियों और सैन्य उपकरणों का निर्यात करने वाला विश्वसनीय राष्ट्र बन चुका है। यह परिवर्तन केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक,वैज्ञानिक,सैन्य और कूटनीतिक शक्ति का भी प्रमाण है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया सहित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ हुई उच्चस्तरीय वार्ताएं इस नई विदेश नीति की सफलता का सशक्त उदाहरण हैं। रक्षा,समुद्री सुरक्षा,व्यापार,तकनीक और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्रों में हुए समझौते यह स्पष्ट करते हैं कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है।

भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है। वर्षों तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक माना जाता था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल रही है। 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान ने रक्षा उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल,अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल,आकाश वायु रक्षा प्रणाली, पिनाका रॉकेट सिस्टम,तेजस लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक रक्षा उपकरण आज विश्व के अनेक देशों का विश्वास जीत रहे हैं। भारत की स्वदेशी अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल आज केवल भारतीय सेना की शक्ति का प्रतीक नहीं हैं,बल्कि विश्व के अनेक देशों की सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम भी बन रही हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध आतंकवाद विरोधी अभियानों में इन हथियारों की प्रभावशीलता ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। यही कारण है कि इंडोनेशिया जैसे महत्वपूर्ण देश अपने सुखोई लड़ाकू विमानों के लिए अस्त्र मिसाइल प्राप्त करना चाहते हैं तथा ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह भारत के रक्षा उद्योग के प्रति बढ़ते वैश्विक विश्वास का प्रमाण है।

इंडोनेशिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। मलक्का जलडमरूमध्य जैसे विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग पर उसकी रणनीतिक स्थिति वैश्विक व्यापार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग केवल दो देशों के संबंधों को मजबूत नहीं करता,बल्कि पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भी नया आयाम देता है।

फ्लैश फ्लड से पहले फ्लैशबैक : एक गलती,पूरी कहानी खत्म

- एक वायरल रील की कीमतः पूरी जिंदगी और परिवार का दर्द
- जोश नहीं,जीवन बचाइए : मानसून में प्रकृति को चुनौती नहीं,सम्मान दीजिए...

प्रो. राकेश कुमार जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

प्रकृति जब रौद्र रूप धारण करती है,तब मनुष्य की सारी शक्ति क्षणभर में प्रभावहीन हो जाती है। मानसून इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यही वर्षा भारत के खेतों में जीवन भरती है,तो कभी भीषण बाढ़ और भूस्खलन बनकर गाँव, सड़कें,पुल और अनगिनत जिंदगियों को लील लेती है। उफनती नदियाँ, विकराल झरने और शांत पहाड़ियाँ पलभर में मौत का मंजर बन जाती हैं। ऐसे समय सबसे अधिक चिंता उन युवाओं की होती है, जो रोमांच के नाम पर जोखिम को ही साहस समझ बैठते हैं। याद रखिए, आप केवल अपने परिवार की उम्मीद नहीं,बल्कि राष्ट्र की अमूल्य शक्ति हैं। इसलिए मानसून के इन तीन-चार महीनों में उफनती नदियों,झरनों,खतरनाक पहाड़ी क्षेत्रों और जोखिम भरे ट्रेकिंग मार्गों से पूरी तरह दूर रहना ही सच्ची समझदारी है। मानसून की खूबसूरती जितनी मोहक दिखती है,उसका खतरा उतना ही गंभीर होता है। भारत के हिमालयी क्षेत्र,पश्चिमी घाट और उत्तर-पूर्व के पर्वतीय इलाकों में हर वर्ष भारी वर्षा,फ्लैश फ्लड और भूस्खलन तबाही मचाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अनुसार, इन आपदाओं में हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है। मौसम विभाग (आईएमडी) लगातार चेतावनियाँ जारी करता है, फिर भी कई युवा रोमांच के आकर्षण में उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। मनाली-लेह मार्ग, हरिशचंद्रगढ़,हरिहर किला,केदारनाथ सहित अनेक पर्वतीय क्षेत्र मानसून में बेहद जोखिमभरे हो जाते हैं। गीली चट्टानों पर एक छोटी-सी चूक या ऊपरी पहाड़ों में हुई बारिश से आया अचानक सैलाब संभलने का मौका तक नहीं देता। जो स्थान कुछ

देर पहले सुरक्षित दिखता है,वही पलभर में मौत का रास्ता बन सकता है। रोमांच का वास्तविक अर्थ जोखिम मोल लेना नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। आज ट्रेकिंग युवाओं के बीच पर्यटन से बढ़कर एक फैशन बन गई है। सोशल मीडिया की आकर्षक तस्वीरें और वीडियो देखकर अनेक लोग यह भूल जाते हैं कि प्रकृति का सुंदर चेहरा पलभर में भयावह रूप भी धारण कर सकता है। फ्लैश फ्लड,फिसलन भरी चढ़ाइयाँ, उफनती नदियाँ और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में अनावश्यक साहस दिखाना उपलब्धि नहीं, लापरवाही है। कई बार रेड अलर्ट और मौसम विभाग की चेतावनियों के बावजूद लोग जोखिम उठाते हैं। इसका परिणाम केवल एक हादसा नहीं होता, बल्कि पूरा परिवार जीवनभर के दुःख और पीड़ा का बोझ उठाता है। इसलिए सच्ची बहादुरी प्रकृति को चुनौती देने में नहीं,उसकी चेतावनियों का सम्मान कर सुरक्षित रहने में है।

हर रोमांचक मंज़िल से पहले अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय है। युवाओं को समझना होगा कि जीवन किसी एक ट्रेक,यात्रा या वायरल वीडियो से कहीं अधिक मूल्यवान है। माता-पिता अपने बच्चों में अपने वर्षों के त्याग,संघर्ष और अनगिनत सपनों का भविष्य देखते हैं। एक क्षण की लापरवाही उन सभी उम्मीदों को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। देश को भी ऐसे युवा चाहिए, जो सुरक्षित रहकर शिक्षा, कौशल और अपनी ऊर्जा से राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। जोश युवावस्था की पहचान है,लेकिन सही दिशा विवेक ही देता है। इसलिए सितंबर-अक्टूबर तक प्रतीक्षा करना,जब मौसम और रास्ते दोनों सुरक्षित हों,कहीं अधिक बुद्धिमानी है। प्रकृति हमेशा रहेगी,अवसर फिर मिलेंगे,लेकिन जीवन दोबारा नहीं मिलेगा।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

सीएमएचओ की जांच में अस्पताल का आयुष्मान पंजीयन नहीं होने की पुष्टि

संयुक्त संचालक बोले... आरोप सही मिले तो लाइसेंस निरस्त होगा...
ग्रामीणों ने कार्ड से राशि निकलने और बिल-रिपोर्ट नहीं मिलने के लगाए आरोप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिस स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में निजी अस्पतालों को नर्सिंग होम एक्ट के नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी है,उसी विभाग की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि एनएच गोयल हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत नहीं है। इसके बावजूद अस्पताल में कथित रूप से आयुष्मान हितग्राहियों का उपचार किए जाने और ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड का उपयोग होने के आरोप सामने आए हैं। यदि जांच में यह साबित होता है कि बिना अधिकृत पंजीयन के आयुष्मान योजना का लाभ लिया गया या मरीजों से राशि वसूली गई,तो यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि सार्वजनिक धन और गरीब मरीजों के अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला होगा। संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. अनिल कुमार शुक्ला ने सीएमएचओ से जांच कराई। 6 जुलाई को प्राप्त रिपोर्ट में अस्पताल का आयुष्मान योजना में पंजीयन नहीं होने की जानकारी दी गई। अब पूरे मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं तथा जिला कलेक्टर को भी पत्र भेजा जा रहा है। विभाग का कहना है कि यदि आरोप सही पाए गए तो अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने सहित नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले की शिकायत करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. डी.के. सोनी का दावा है कि बलरामपुर जिले के ग्राम कोदौरा सहित कई ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि उन्हें मुफ्त इलाज का भरोसा देकर अस्पताल ले जाया गया, आयुष्मान कार्ड का उपयोग किया गया, लेकिन इलाज के बाद न मेडिकल रिपोर्ट दी गई और न ही कोई बिल उपलब्ध कराया गया। इन शिकायतों के आधार पर विभागीय जांच कराई गई।

सबसे बड़ा सवाल...अगर पंजीयन नहीं था तो सिस्टम सोता क्यों रहा?

इस पूरे प्रकरण ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यदि अस्पताल वास्तव में आयुष्मान योजना में पंजीकृत नहीं था,तो फिर वहां कथित रूप से आयुष्मान हितग्राहियों का इलाज कैसे होता रहा? क्या संबंधित विभागों ने कभी सत्यापन नहीं किया? क्या आयुष्मान योजना की निगरानी केवल कागजों तक सीमित है? और यदि मरीजों के कार्ड का दुरुपयोग हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी केवल अस्पताल की होगी या निगरानी तंत्र की भी तय होगी? यदि जांच में ग्रामीणों के आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केवल एक अस्पताल का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे स्वास्थ्य प्रशासन की जवाबदेही का प्रश्न बन जाएगा।

सिर्फ अस्पताल नहीं,जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आए : जनहित की दृष्टि से अब जांच केवल अस्पताल तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित अवधि में निरीक्षण किसने किया, किन अधिकारियों ने निगरानी की,और यदि अनियमितताएं थीं तो उन पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होना आवश्यक है।

जांच पूरी होने तक आरोप,लेकिन जवाब जरूरी : फिलहाल विभागीय जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। अस्पताल का पक्ष इस समाचार के प्रकाशन तक प्राप्त नहीं हो सका है। अस्पताल की ओर से प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

घटती-घटना की टिप्पणी...

नियमों की किताब हाथ में लेकर विभाग निजी अस्पतालों को चेतावनी तो दे रहा है,लेकिन सवाल यह है कि जब कथित अनियमितताएं हो रही थीं तब निगरानी तंत्र कहां था? यदि बिना पंजीयन के कोई संस्थान आयुष्मान योजना से जुड़ी गतिविधियां करता रहा और विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी,तो यह केवल अस्पताल की नहीं, पूरे सिस्टम की विफलता है। यदि सरकार वास्तव में गरीबों के स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा करना चाहती है,तो केवल अस्पताल पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। यह भी जांचना होगा कि आखिर किसकी लापरवाही या संरक्षण में ऐसी स्थिति बनी। जनता को दिखावटी सख्ती नहीं, बल्कि ऐसी निष्पक्ष जांच चाहिए जिसमें अस्पताल के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी सामने आए। तभी यह स्पष्ट होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था मरीजों के लिए काम कर रही है या फिर केवल कागजी नियमों के सहारे चल रही है।

15 प्रकरणों में जब्त मादक पदार्थों का किया गया नष्टीकरण
44 किलो गांजा सहित हजारों इंजेक्शन-टैबलेट नष्ट

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत विभिन्न मामलों में जब्त मादक पदार्थों का नियमानुसार नष्टीकरण किया। जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति के मार्गदर्शन में सूरजपुर जिले के नयनपुर गिरवरगंज स्थित इंद्रा पावर जैन प्राइवेट लिमिटेड परिसर में यह कार्रवाई विधिवत संपन्न हुई। कार्रवाई के दौरान जिले के कुल 15 प्रकरणों में जब्त 44.155 किलोग्राम गांजा, 1,478 इंजेक्शन, 2,610 टैबलेट तथा 110 कफ सिरप को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया। यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप की गई। नष्टीकरण प्रक्रिया की निगरानी ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष एवं डीआईजी-सह-एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) ने की। समिति के सदस्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लों,जिला आबकारी अधिकारी लक्ष्मीकांत गायकवाड़ तथा पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे। पूरी कार्रवाई की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी कराई गई। नष्टीकरण से पूर्व सभी 15 प्रकरणों की विस्तृत सूची एवं आवश्यक दस्तावेज समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए। साथ ही संबंधित विभागों एवं माननीय न्यायालय को नियमानुसार अग्रिम सूचना भी दी गई थी। इस दौरान थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी,डीसीआरबी शाखा प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक उमाशंकर पाण्डेय, सहायक उपनिरीक्षक गंभीर साय,प्रधान आरक्षक अनिल तिर्की तथा आरक्षक अजय यादव सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

12वीं में शीना मेहता बनीं जिले की टॉपर,
मॉन्टफोर्ट स्कूल में मेधावियों का भव्य सम्मान

97.2% अंक हासिल कर जिले में लहराया परचम,10वीं में समर्थ वराडे ने 96.6% के साथ विद्यालय में किया टॉप;आईजी दीपक कुमार झा बोले...सफलता का असली आधार अनुशासन,चरित्र और निरंतर परिश्रम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

शिक्षा केवल अच्छे अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं,बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, अनुशासन और जीवन मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। इसी सोच को साकार करते हुए मॉन्टफोर्ट स्कूल,अंबिकापुर में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में भव्य एवं गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए शील्ड एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने की प्रेरणा दी। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विद्यालय के बैंड दल ने आकर्षक धुनों के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने स्वागत गीत,मनमोहक नृत्य,समूहगान तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समारोह को यादगार बना दिया। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत एक प्रेरणादायी नाटक ने यह संदेश दिया कि कठिन परिश्रम,आत्मविश्वास,सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प के बल पर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। नाटक की प्रस्तुति ने अभिभावकों और अतिथियों की खूब सराहना बटोरी। कार्यक्रम का सबसे गौरवपूर्ण क्षण तब आया जब कक्षा 12वीं की छात्रा शीना मेहता को 97.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिले की टॉपर बनने पर विशेष सम्मान दिया गया। जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई,पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शीना की इस उपलब्धि ने न केवल विद्यालय,बल्कि पूरे अंबिकापुर जिले का गौरव बढ़ाया। वहीं कक्षा 10वीं में समर्थ वराडे ने 96.6 प्रतिशत अंक अर्जित कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। समारोह में अन्य मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। कक्षा 12वीं में आयुष ठाकुर और दिव्या तिग्गा ने 92.4-92.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान हासिल किया। वहीं कक्षा 10वीं में सृष्टि चौधरी और तृप्ति गुप्ता ने 95.2-95.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए,जबकि स्नेहा टोप्पो ने 93.6 प्रतिशत अंक अर्जित कर विद्यालय का नाम रोशन किया। सभी विद्यार्थियों को शील्ड,प्रशस्ति-पत्र एवं शुभकामनाओं के साथ सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता,शिक्षकों और विद्यालय परिवार को दिया। उन्होंने कहा कि नियमित अध्ययन,समय का बेहतर प्रबंधन, शिक्षकों का मार्गदर्शन और परिवार का सहयोग उनकी सफलता की सबसे बड़ी ताकत रहे। विद्यार्थियों ने जूनियर छात्रों को भी लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने की प्रेरणा दी। मुख्य अतिथि दीपक कुमार झा ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि परीक्षा के अंक जीवन की सफलता का अंतिम पैमाना नहीं होते। वास्तविक सफलता उस व्यक्ति को मिलती है, जो अनुशासन,ईमानदारी, मजबूत चरित्र और निरंतर सीखने की इच्छा को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार करियर का चयन करें तथा केवल दूसरों की देखा-देखी निर्णय न लें। उन्होंने असफलताओं को जीवन का महत्वपूर्ण शिक्षक बताते हुए कहा कि हर चुनौती व्यक्ति को और अधिक मजबूत बनाती है। उन्होंने सोशल मीडिया और इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों से तकनीक का सकारात्मक एवं जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम ज्ञान का बड़ा स्रोत है,लेकिन इसका विवेकपूर्ण उपयोग ही भविष्य को बेहतर बना सकता है। उन्होंने अभिभावकों से भी आग्रह किया कि वे बच्चों के साथ संवाद बनाए रखें और उनकी गतिविधियों पर सकारात्मक नजर रखें ताकि वे सही दिशा में आगे बढ़ सकें। विद्यालय के प्राचार्य एस. गैब्रियल ने स्वागत भाषण में कहा कि किसी भी विद्यार्थी की सफलता केवल परीक्षा के अंकों तक सीमित नहीं होती,बल्कि उसका चरित्र,व्यवहार, अनुशासन और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करने और निरंतर अभ्यास करते रहने की सलाह दी। भगवद्गीता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही सोच जीवन में स्थायी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। समारोह में बड़ी संख्या में अभिभावक,शिक्षक,विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान मेधावी विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर गर्व और उत्साह का वातावरण बना रहा। सम्मान समारोह ने यह संदेश दिया कि मेहनत,अनुशासन, समर्पण और सकारात्मक सोच के बल पर कोई भी विद्यार्थी अपने सपनों को साकार कर सकता है। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के बाद राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

माता नाथल देवी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए समिति गठित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

ग्राम बेनीपुर, पंचायत रनपुर खुर्द स्थित प्राचीन आस्था केंद्र माता नाथल देवी मंदिर के जीर्णोद्धार एवं भव्य निर्माण के लिए माता नाथल देवी मंदिर निर्माण एवं जीर्णोद्धार समिति का गठन किया गया है। समिति के संरक्षक जिला पंचायत सदस्य दिव्या सिंह सिसोदिया एवं जितेंद्र सिंह (सोनपुर), अध्यक्ष गौटिया अर्जुन पटेल, उपाध्यक्ष सतीष यादव तथा सचिव हरिशंकर बनाए गए हैं। अध्यक्ष गौटिया अर्जुन पटेल ने बताया कि माता नाथल देवी मंदिर क्षेत्र की प्राचीन धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। परंपरा के अनुसार चैत्र एवं शारदीय नवरात्र में माँ महामाया की पूजा-अर्चना माता नाथल देवी स्थल से चुनरी प्रस्थान होने के बाद ही पूर्ण मानी जाती है। मंदिर में आज भी बैगा परंपरा के अनुसार पूजा-अर्चना की जाती है और बैगा गुनिया के मंत्रोच्चार में माता नाथल देवी का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर के विकास के लिए पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल द्वारा 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठजनों और ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार कर इसे एक व्यवस्थित एवं भव्य धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। समिति में ननका बैगा, पंडा ललन प्रसाद, चंदर यादव, सुखलाल रजवाड़े, राजू यादव, भदर यादव, डिलेश्वर पैकरा, ललित रजवाड़े, नंदकेश्वर रजवाड़े सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों को सदस्य बनाया गया है। समिति ने सभी श्रद्धालुओं एवं ग्रामवासियों से मंदिर निर्माण एवं संरक्षण अभियान में सहयोग करने की अपील की है।

किरायेदारों के सत्यापन की मांग के बाद हरकत में पुलिस,जिलेभर में चला सघन अभियान...

पार्षद आलोक दुबे ने आईजी को सौंपा था ज्ञापन,बाहरी राज्यों से आए लोगों की जांच और मकान मालिकों की जवाबदेही तय करने की उठाई थी मांग

125 मकानों व प्रतिष्ठानों में जांच, 450 लोगों के पहचान पत्रों का सत्यापन,संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

शहर में बाहरी राज्यों से आए किरायेदारों के सत्यापन की मांग उठने के बाद सरगुजा पुलिस ने जिलेभर में सघन जांच अभियान चलाया। नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद आलोक दुबे ने हाल ही में सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को ज्ञापन सौंपकर अंबिकापुर में बिना पुलिस सत्यापन रह रहे बाहरी राज्यों के किरायेदारों और विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत लोगों का व्यापक सत्यापन कराने की मांग की थी। इसके बाद डीआईजी एवं एसएसपी के निर्देशन में पुलिस ने जिलेभर में विशेष अभियान चलाकर किरायेदारों,बाहरी व्यक्तियों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत लोगों के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। पार्षद आलोक दुबे ने अपने ज्ञापन में कहा था कि गांधीनगर, कोतवाली और मणिपुर थाना क्षेत्रों सहित शहर के कई इलाकों में बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के लोग किराये पर रह रहे हैं,लेकिन उनके संबंध में न तो मकान मालिकों के पास पूरी जानकारी है और न ही पुलिस रिकॉर्ड में समुचित विवरण उपलब्ध है। उन्होंने मांग की थी कि तीनों थाना क्षेत्रों की संयुक्त टीम बनाकर प्रत्येक किरायेदार का भौतिक सत्यापन किया जाए,उसकी पहचान,गृह जिला,रोजगार और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कराई जाए। साथ ही किरायेदारों का सत्यापन नहीं कराने वाले मकान मालिकों की जिम्मेदारी भी तय की जाए। पार्षद ने ज्ञापन में यह भी कहा था कि समय रहते प्रभावी सत्यापन नहीं होने पर भविष्य में असामाजिक तत्व शहर की शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं। ज्ञापन की प्रतिलिपि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई थी।

पुलिस ने चलाया विशेष सत्यापन अभियान: पार्षद आलोक दुबे की मांग के बीच डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देशन में सभी थाना और चौकी प्रभारियों को बाहरी राज्यों से आए लोगों, किरायेदारों और मुसाफिरों की जांच के निर्देश दिए गए।

इसके बाद जिलेभर में किराये के मकानों, होटलों, ढाबों,पान ठेलों,गुमटियों,व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा बस-ट्रक संचालकों के यहां कार्यरत चालक,कंडक्टर और क्लीनरों का सत्यापन किया गया। पुलिस ने मकान मालिकों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को निर्देशित किया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को किराये पर रखने या काम पर रखने से पहले उसकी जानकारी संबंधित थाने में उपलब्ध कराएं तथा मुसाफिरी दर्ज कराएं। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए भी कहा गया।

125 स्थानों पर जांच,450 लोगों के दस्तावेज खंगाले : सघन अभियान के दौरान पुलिस ने 125 मकानों,होटलों,ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जांच की। करीब 450 लोगों के पहचान पत्रों का सत्यापन किया गया। पुलिस ने आसपास के नागरिकों से भी अपील की कि यदि उनके क्षेत्र में कोई संदिग्ध व्यक्ति या बाहरी किरायेदार रह रहा हो तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस ने हेल्पलाइन 9479193599 और डायल 112 पर सूचना देने की अपील करते हुए कहा है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं समीर आजम आ0 मुर्तजा उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी-ग्राम खाराकोना, थाना लुण्ड्रा, तहसील लुण्ड्रा, जिला एवं जिला सरगुजा (छ0ग0) का स्थायी निवासी है। अपने नाबालिग पुत्री मयरा सिद्दिकी से बदलकर अमायरा सिद्दिकी करवाना चाहता है। जिसका आधार नम्बर - 2703 66956400 है।अपने पुत्री का नाम बदलकर यदि कोई गैर कानूनी काम करता हूं तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। मेरी पुत्री का सही नाम अग्रेंजी में AMAIRA SIDDIQUE है एवं जन्म प्रमाण पत्र में भी AMAIRA SIDDIQUE अंकित है। यह कि मुझे एवं मेरी पत्नी निलोफर सिद्दीकी को हमारे नाबालिग पुत्री के नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपने पूरे होशोहवास में रहकर हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

शपथग्रहिता
समीर आजम

जीएसटी नियमों का पालन करें व्यापारी,नहीं तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें

सत्यापन अभियान के बीच टैक्स बार एसोसिएशन ने जारी की एडवाइजरी,व्यापारियों से दस्तावेज दुरुस्त रखने की अपील...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले में जीएसटी विभाग द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच टैक्स बार एसोसिएशन सरगुजा ने व्यापारियों से जीएसटी के अनिवार्य नियमों का पालन करने और सभी आवश्यक दस्तावेज व्यवस्थित रखने की अपील की है,ताकि जांच के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। टैक्स बार एसोसिएशन सरगुजा की आयोजित बैठक में अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने कहा कि जिन व्यापारियों ने जीएसटी पंजीयन कराया है, वे अपनी दुकान के बाहर फर्म का नाम,पता,प्रोपराइटर का नाम एवं जीएसटी नंबर अंकित बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाएं। साथ ही जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रतिष्ठान में प्रदर्शित रखें। उन्होंने व्यापारियों से क्रय एवं विक्रय के सभी बिल सुरक्षित रखने, 200 रुपये से अधिक मूल्य की प्रत्येक बिक्री का बिल जारी करने तथा बिना बिल के किसी भी प्रकार का माल खरीदने या बेचने से बचने की सलाह दी। इसके अलावा ई-वे बिल बनाते समय बिल,वाहन नंबर एवं अन्य विवरणों का मिलान करने तथा लेन-देन यथासंभव बैंकिंग माध्यम से करने का आग्रह किया।

जनहित में जरूरी है नियमों का पालन : टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी संबंधी नियमों का पालन केवल कानूनी बाध्यता ही नहीं, बल्कि पारदर्शी व्यापार व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैध बिल जारी करने से उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित रहते हैं, वहीं व्यापारियों को भी भविष्य में किसी जांच या कर संबंधी विवाद की स्थिति में सुविधा मिलती है। बैठक में टैक्स बार एसोसिएशन के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ताओं तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी अपने सुझाव दिए और सभी व्यापारियों से समय पर रिटर्न दाखिल करने तथा रिकॉर्ड अद्यतन रखने की अपील की।

जिसे जेल में होना था,वह वोटर लिस्ट में कैसे पहुंच गया? 13 साल तक फरार गैंगस्टर का शहर में 'वैध' जीवन,अब कटघरे में पूरा तंत्र

13 साल तक शहर में छिपा रहा उम्रकैद का गैंगस्टर...वोटर आईडी भी बन गया...अब कटघरे में पूरा सिस्टम

पहले खबर को नजरअंदाज किया,फिर एफआईआर लिखी...अब पुलिस पूछ रही है...आरोपी गया कहां?

पुलिस की गिरफ्त से छूटा सजायाफ्ता हत्यारा
अब जांच के घेरे में स्थानीय संपर्क और पुलिस समन्वय

झारखंड से भागा,अंबिकापुर में बसा...अब पुलिस पूछ रही है-गैंगस्टर गया कहां?

अंबिकापुर में मचा हड़कंप : आजीवन कारावास प्राप्त दोषी पुलिस की गिरफ्त से निकला...

उम्रकैद का फरार गैंगस्टर,वोटर आईडी और 13 साल की चुप्पी... आखिर जिम्मेदार कौन?

दैनिक घटती-घटना के खुलासे के बाद एफआईआर...लेकिन सवाल अब भी कायम, गैंगस्टर कैसे बना 'वैध नागरिक'?

सिर्फ गैंगस्टर नहीं,पूरा सिस्टम जांच के घेरे में...13 साल तक अंबिकापुर में कैसे छिपा रहा साबिर आलम?

वोटर आईडी से लेकर करोड़ों के कारोबार तक...उम्रकैद के फरार गैंगस्टर ने कैसे बनाया अपना नेटवर्क?

छह दिन बाद जागी पुलिस,तब तक गैंगस्टर भी फरार और संरक्षण देने वाले भी गायब

सजायाफ्ता गैंगस्टर का वोटर आईडी कैसे बना? एफआईआर के बाद उठे कई कानूनी और प्रशासनिक सवाल

13 साल तक पहचान छिपाकर रहा फरार गैंगस्टर...अब पुलिस,प्रशासन और चुनावी तंत्र पर उठे सवाल

-संवाददाता-

अंबिकापुर,09 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। झारखंड के धनबाद स्थित बहुचर्चित वासेपुर दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा प्राप्त फरार गैंगस्टर साबिर आलम का मामला अब केवल एक अपराधी की फरारी का मामला नहीं रह गया है,यह अब प्रशासनिक जवाबदेही,पुलिस की कार्यप्रणाली, पहचान दस्तावेजों की वैधता,चुनावी रिकॉर्ड,स्थानीय सत्यापन तंत्र,अंतरराज्यीय पुलिस समन्वय और कथित संरक्षण नेटवर्क तक पहुंच चुका है। इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 29 जून 2026 को हुई घटना की जानकारी सबसे पहले दैनिक घटती-घटना को मिली और 1 जुलाई 2026 के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित भी हुई,इसके बाद भी स्थानीय पुलिस ने तत्काल कोई अपराध दर्ज नहीं किया,दूसरी ओर, झारखंड पुलिस लगातार इस मामले में संपर्क और कार्रवाई का प्रयास करती रही। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से तत्काल प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई, बाद में 5 जुलाई 2026 को दैनिक घटती-घटना ने दोबारा इस विषय को प्रमुखता से प्रकाशित किया, तब तक कई अन्य मीडिया संस्थानों में भी यह मामला प्रकाशित हो चुका था, इसके बाद थाना अंबिकापुर में अपराध क्रमांक 454/2026 दर्ज किया गया, जिसमें मोमिनपुरा निवासी बस संचालक बैदुल खान एवं अन्य के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 249 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया, लेकिन अपराध दर्ज होने के साथ ही अनेक ऐसे प्रश्न सामने आ गए, जिनका उत्तर अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है।

सबसे बड़ा सवाल—एक उम्रकैद का फरार अपराधी आखिर 13 वर्षों तक शहर में कैसे रहा?

यदि एफआईआर में दर्ज तथ्यों के अनुसार साबिर आलम वर्ष 2013 से अंबिकापुर में पहचान छिपाकर रह रहा था,तो यह केवल उसकी चतुराई का मामला नहीं माना जा सकता,सवाल यह है कि एक बाहरी व्यक्ति वर्षों तक शहर में रहा,मकान बनाया,कारोबार बढ़ाया,आर्थिक गतिविधियां संचालित कीं और फिर भी किसी एजेंसी को उसकी वास्तविक पहचान का पता नहीं चला? यदि ऐसा हुआ, तो स्थानीय सत्यापन व्यवस्था, पुलिस की सूचना प्रणाली और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक है।

वोटर आईडी कार्ड कैसे बना? क्या अन्य सरकारी दस्तावेज भी तैयार हुए?

इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब चुनावी दस्तावेजों और पहचान पत्रों से जुड़ गया है,यदि एक आजीवन कारावास का सजायाफ्ता और फरार अपराधी अंबिकापुर में वर्षों तक रह रहा था,तो उसका वोटर आईडी कार्ड कैसे बना? क्या आधार कार्ड भी बना? क्या राशन कार्ड,बैंक खाते,मोबाइल सिम और अन्य सरकारी दस्तावेज भी तैयार हुए? क्या स्थानीय स्तर पर निवास सत्यापन किया गया था? यदि किया गया था, तो किसने किया? चुनाव आयोग वर्तमान में विशेष गहन पुनरीक्षण चला रहा है,जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है,ऐसे समय यदि किसी फरार सजायाफ्ता अपराधी का नाम मतदाता सूची में पाया जाता है, तो यह केवल एक प्रशासनिक त्रुटि नहीं बल्कि पूरे सत्यापन तंत्र पर प्रश्नचिह्न है।

दैनिक घटती-घटना ने सबसे पहले किया था खुलासा, फिर भी छह दिन तक नहीं जागी पुलिस- इस मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू पुलिस की कार्रवाई का समय है, दैनिक घटती-घटना ने 1 जुलाई को खबर प्रकाशित की, 5 जुलाई को पुनः विस्तृत समाचार प्रकाशित किया,झारखंड पुलिस लगातार संपर्क में थी, अन्य मीडिया संस्थानों ने भी मामला उठाया,इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर अपराध दर्ज होने में छह दिन का समय लग गया, यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है यदि पहले दिन ही विधिवत अपराध दर्ज कर तत्काल कार्रवाई होती,तो क्या साबिर आलम आज भी फरार रहता? क्या उसे संरक्षण देने वाले लोग भी फरार हो पाते? कई नागरिकों का मानना है कि शुरुआती कार्रवाई में हुई देरी का लाभ आरोपियों को मिला।

एफआईआर दर्ज हुई,लेकिन उसमें भी उठ रहे हैं कई तकनीकी प्रश्न-अपराध दर्ज होना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन एफआईआर पढ़ने के बाद कई कानूनी प्रश्न भी सामने आ रहे हैं,एफआईआर में समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर जानकारी मिलने का उल्लेख है,जबकि सार्वजनिक रूप से यह भी कहा गया कि धनबाद पुलिस आरोपी की तलाश में अंबिकापुर आई थी,ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि क्या धनबाद पुलिस के आधिकारिक पत्राचार, वारंट अथवा दस्तावेजों को भी विवेचना का आधार बनाया गया? कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायालय में अखबार की खबर स्वयं स्वतंत्र साक्ष्य नहीं होती, बल्कि उसे अन्य साक्ष्यों से प्रमाणित करना पड़ता है, इसी प्रकार एफआईआर में आरोपी का विस्तृत परिचय, शिकायतकर्ता का स्पष्ट उल्लेख तथा अन्य बिंदुओं को लेकर भी कई तकनीकी सवाल उठाए जा रहे हैं।

क्या केवल बैदुल खान ने संरक्षण दिया या पूरा नेटवर्क सक्रिय था?- एफआईआर में बैदुल खान एवं अन्य के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है, यहीं से जांच का दायरा और बड़ा हो जाता है,यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक फरार रहकर शहर में सक्रिय रहा,तो क्या केवल एक व्यक्ति के सहयोग से यह संभव था? क्या अन्य स्थानीय संपर्क भी थे? क्या आर्थिक सहयोग मिला? क्या व्यवसायिक गतिविधियों में साझेदार थे? क्या दस्तावेज बनवाने में भी किसी ने सहयोग किया? अब जांच का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही माना जा रहा है।

फरार गैंगस्टर भी गायब, संरक्षण देने के आरोपी भी लापता-वर्तमान स्थिति और भी चिंताजनक बताई जा रही है,साबिर आलम अब भी फरार है,उसे संरक्षण देने के आरोप में नामजद बैदुल खान भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है,अन्य संदिग्ध सहयोगियों के संबंध में भी पुलिस की ओर से कोई स्पष्ट सफलता सामने नहीं आई है,यानी मुख्य अपराधी भी फरार,उसे संरक्षण देने का आरोपी भी फरार,और जिन लोगों की भूमिका की चर्चा हो रही है, वे भी पुलिस की पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में शहर में यह चर्चा तेज है कि क्या केवल अपराध दर्ज कर देने से यह मामला अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचेगा,या वास्तव में आरोपियों तक कानून पहुंचेगा।

क्या पुलिस अब पूरा नेटवर्क उजागर करेगी?- यह मामला अब केवल एक हत्या के दोषी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है,जांच को यह भी स्पष्ट करना होगा क्या शहर में कोई संगठित संरक्षण तंत्र सक्रिय था? क्या आर्थिक नेटवर्क विकसित किया गया? क्या सरकारी दस्तावेज फर्जी तरीके से बनवाए गए? क्या स्थानीय स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया में लापरवाही हुई? क्या किसी सरकारी कर्मचारी की भूमिका रही? यदि इन प्रश्नों के उत्तर नहीं खोजे गए, तो पूरा मामला अधूरा माना जाएगा।

अब उठ रही एसआईटी जांच की मांग- मामले की गंभीरता को देखते हुए कई सामाजिक संगठनों,अधिवक्ताओं और नागरिकों द्वारा विशेष जांच दल गठित करने की मांग की जा रही है, मांग है कि केवल पुलिस ही नहीं बल्कि निर्वाचन विभाग, राजस्व विभाग,परिवहन विभाग,नगर निगम, आर्थिक अपराध अन्वेषण एजेंसियां, भी अपने-अपने स्तर पर जांच करें।

शहर का सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनुत्तरित है-यदि एक आजीवन कारावास प्राप्त भगोड़ा अपराधी 13 वर्षों तक शहर में नई पहचान के साथ रह सकता है...यदि वह आर्थिक गतिविधियां चला सकता है...यदि उसके दस्तावेज बन सकते हैं...यदि वह मतदाता सूची तक पहुंच सकता है...यदि उसके विरुद्ध कार्रवाई होने से पहले वह फिर फरार हो सकता है...तो फिर सवाल केवल साबिर आलम का नहीं है, सवाल उस पूरी व्यवस्था का है,जिसे ऐसे अपराधियों की पहचान बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी।

अब जनता जानना चाहती है...- क्या पुलिस साबिर आलम को गिरफ्तार करेगी?

क्या बैदुल खान और अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी होगी? क्या वोटर आईडी सहित सभी दस्तावेजों की जांच होगी? क्या दस्तावेज बनाने वालों की भूमिका सामने आएगी? क्या पूरे आर्थिक नेटवर्क का खुलासा होगा? या फिर यह मामला भी केवल एक एफआईआर और कुछ फाइलों तक सीमित रह जाएगा? अब निगाहें जांच पर हैं...क्योंकि इस बार कटघरे में सिर्फ एक फरार गैंगस्टर नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था खड़ी दिखाई दे रही है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

अनुलग्नक-I

खानपान ईकाई निविदा क्र-E-Auction No.- COM/Catg./E Auction/ Premium Brand Catering Outlet/2026

बिलासपुर मंडल के **बिलासपुर, रायगढ, अनुपपुर, शहडोल और अम्बिकापुर** रेलवे स्टेशनों के प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट के लिए ई-नीलामी (निविदा) आमंत्रित की गई है। कैटलॉग पहले ही IREPS वेबसाइट (**https://ireps.gov.in**) पर दिनांक **04.07.2026** को प्रकाशित की जा चुकी है। विवरण निम्मानुसार है

Catalogue no.	श्रेणी	नीलामी आरंभ	लॉट क्रमांक	लॉट विवरण	अनुबंध अवधि
BSP-PBCO-2	विविध-स्थैतिक-सेवा प्रीमियम स्टोर	20.07.2026 10.00	MSS-BSP-BSP-PS-143-26-1 (विविध-स्थैतिक-सेवा प्रीमियम स्टोर)	Lot for PBCO No- BSP-PB02-BSP-PF-2/3, बिलासपुर रेलवे स्टेशन (बिलासपुर डिवीजन) पर प्रीमियम ब्रांड खानपान आउटलेट का आवंटन।	1826 दिन
	विविध-स्थैतिक-सेवा प्रीमियम स्टोर	20.07.2026 10.00	MSS-BSP-BSP-PS-149-26-1 (विविध-स्थैतिक-सेवा प्रीमियम स्टोर)	Lot for PBCO No- BSP-PB03-BSP-PF-4/5, बिलासपुर रेलवे स्टेशन (बिलासपुर डिवीजन) पर प्रीमियम ब्रांड खानपान आउटलेट का आवंटन।	1826 दिन
	विविध-स्थैतिक-सेवा प्रीमियम स्टोर	20.07.2026 10.00	MSS-BSP-RIG-PS-145-26-1 (विविध-स्थैतिक-सेवा प्रीमियम स्टोर)	Lot for PBCO No- BSP-PB04-RIG-PF- 2/3, रायगढ़ रेलवे स्टेशन (बिलासपुर डिवीजन) पर प्रीमियम ब्रांड खानपान आउटलेट का आवंटन।	1826 दिन
	विविध-स्थैतिक-सेवा प्रीमियम स्टोर	20.07.2026 10.00	MSS-BSP-APR-PS-146-26-1 (विविध-स्थैतिक-सेवा प्रीमियम स्टोर)	Lot for PBCO No- BSP-PB05-APR-PF-3/4, अनुपपुर रेलवे स्टेशन (बिलासपुर डिवीजन) पर प्रीमियम ब्रांड खानपान आउटलेट का आवंटन।	1826 दिन
	विविध-स्थैतिक-सेवा प्रीमियम स्टोर	20.07.2026 10.00	MSS-BSP-SDL-PS-147-26-1 (विविध-स्थैतिक-सेवा प्रीमियम स्टोर)	Lot for PBCO No- BSP-PB06-SDL-PF-2/3, अनुपपुर रेलवे स्टेशन (बिलासपुर डिवीजन) पर प्रीमियम ब्रांड खानपान आउटलेट का आवंटन।	1826 दिन
	विविध-स्थैतिक-सेवा प्रीमियम स्टोर	20.07.2026 10.00	MSS-BSP-ABKP-PS-148-26-1 (विविध-स्थैतिक-सेवा प्रीमियम स्टोर)	Lot for PBCO No- BSP-PB07-ABKP-PF-1 अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन (बिलासपुर डिवीजन) पर प्रीमियम ब्रांड खानपान आउटलेट का आवंटन।	1826 दिन

सीपीआर/10/271

मंडल वाणिज्य प्रबंधक
द.पू.म.रेलवे, बिलासपुर

R.O.No.56268

स्वस्तिक ढाबा में जुए पर पुलिस का छापा...8 जुआरी गिरफ्तार,8 लाख से अधिक का मशरुका जब्त

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,09 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा पुलिस ने जुआ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांधीनगर थाना क्षेत्र के चठीरमा स्थित स्वस्तिक ढाबा में छापा मारकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से नकद राशि, ताश की गड्डी सहित एक चारपहिया एवं चार दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। जब्त मशरुका की कुल अनुमानित कीमत 8 लाख रुपये से अधिक बताई गई है। पुलिस के अनुसार डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देश पर जिले में जुआ एक्ट के मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 9 जुलाई 2026 को गांधीनगर पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चठीरमा स्थित स्वस्तिक ढाबा के परछी में कुछ लोग ताश के पत्तों से हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 8 व्यक्ति जुआ खेलते

हुए पकड़े गए। उनके कब्जे से 52 पत्ती ताश, 50,900 रुपये नगद, एक चारपहिया वाहन और चार दोपहिया वाहन जब्त किए गए। कुल जब्त मशरुका की अनुमानित कीमत 8 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 की धारा 3(2) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी

1. प्रेम सिंह (38),निवासी केदारपुर, अंबिकापुर
2. शंकर मिस्त्री (32),निवासी भगवानपुर,गांधीनगर
3. दीपक पकरिया (43),निवासी खलिबा,गांधीनगर
4. खगेश राम (40),निवासी चठीरमा, गांधीनगर
5. कोमल सिंह (30),निवासी चठीरमा, गांधीनगर
6. गोपाल भद (25),निवासी संजयनगर आमापारा,जयनगर
7. योगेंद्र प्रसाद (32),निवासी चठीरमा,गांधीनगर
8. कार्तिक दास (42),निवासी चठीरमा,गांधीनगर

C M Y K

17 साल की बेटी ने क्यों चुनी मौत? बैकुंठपुर की घटना ने पुलिस,व्यवस्था और परवरिश-तीनों पर खड़े किए बड़े सवाल

चोरी के आरोप से मौत तक : नाबालिग की आत्महत्या ने खोली व्यवस्था की कई परतें...

आई-मार्ट विवाद के बाद नाबालिग की आत्महत्या,एफआईआर में गंभीर आरोप, पुलिस की भूमिका भी जांच के घेरे में...

बैकुंठपुर की दर्दनाक घटना: एक बेटी चली गई,अब जवाब मांग रहे हैं कई सवाल

क्या हम अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बना पा रहे हैं? बैकुंठपुर की घटना ने झकझोरा समाज...

नाबालिग की आत्महत्या,एफआईआर में दुकान संचालकों पर आरोप,पुलिस की भूमिका और परवरिश पर भी उठे सवाल...

एक आरोप,कथित प्रताड़ना और खत्म हो गई जिंदगी...बैकुंठपुर की घटना ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया...

एफआईआर में दुकान संचालकों पर गंभीर आरोप,पुलिस को पहले से जानकारी होने का दावा...

घटना ने परिवार,समाज और व्यवस्था-तीनों को आत्ममंथन के लिए किया मजबूर...

-रवि सिंह-

कोरिया,09 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के बैकुंठपुर में 17 वर्षीय आदिवासी नाबालिग किशोरी की आत्महत्या ने पूरे जिले को झकझोर दिया है,इस मामले में दर्ज एफआईआर ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए है,शिकायतकर्ता ने आई-मार्ट दुकान संचालकों पर मानसिक प्रताड़ना,कथित रूप से धन की मांग,स्कूटी जब्त करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने जैसे आरोप लगाए हैं, वहीं, एफआईआर में यह भी दावा किया गया है कि घटना की जानकारी पुलिस को पहले से थी, पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है,हालांकि, एफआईआर में दर्ज सभी आरोप शिकायतकर्ता के कथन पर आधारित हैं,इनकी पुष्टि पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।

क्या है पूरा मामला?- एफआईआर के अनुसार 17 वर्षीय नाबालिग आदिवासी किशोरी बैकुंठपुर स्थित आई-मार्ट दुकान गई थी,आरोप है कि वहां उस पर चोरी का आरोप लगाया गया,शिकायत में कहा गया है कि इसके बाद उसे कई घंटों तक दुकान में बैठाकर रखा गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया,एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि किशोरी से अलग-अलग स्थानों पर हस्ताक्षर कराए गए तथा उससे लिखित रूप में कथित स्वीकारोक्ति भी लिखवाई गई,आरोप है कि उसकी स्कूटी भी दुकान संचालकों ने अपने कब्जे में रख ली।

20 हजार से 50 हजार रुपये तक मांगने का आरोप-शिकायतकर्ता का आरोप है कि पहले लगभग 20 हजार रुपये देने की बात कही गई, बाद में कथित रूप से 50 हजार रुपये तक की मांग की गई, परिवार का कहना है कि इतनी बड़ी राशि तत्काल देना संभव नहीं था,एफआईआर में आरोप है कि राशि जमा होने तक स्कूटी वापस नहीं देने की बात कही गई,इन आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

घटना ने परवरिश और मानसिक मजबूती पर भी खड़े किए सवाल-यह दुखद घटना केवल पुलिस या कथित प्रताड़ना तक सीमित नहीं है,इसने समाज और परिवारों के सामने भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है क्या आज हम अपने बच्चों को मानसिक रूप से इतना मजबूत बना पा रहे हैं कि वे कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकें? यह कहना उचित नहीं होगा कि किसी एक परिवार की परवरिश इस घटना के लिए जिम्मेदार थी, बिना जांच और प्रमाण के ऐसा निष्कर्ष निकालना गलत होगा,लेकिन यह घटना अवश्य संकेत देती है कि आज के समय में हर परिवार को बच्चों के भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर पहले से कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है,आज बच्चे पढ़ाई,सामाजिक प्रतिस्पर्धा,सोशल मीडिया,साथियों के दबाव, असफलता के डर और सार्वजनिक अपमान जैसी अनेक चुनौतियों से गुजर रहे हैं,ऐसे में अभिभावकों की जिम्मेदारी केवल अच्छी शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराना नहीं,बल्कि उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाना भी है,विशेषज्ञ मानते हैं कि बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव,अत्यधिक चुप्पी,अकेले रहने की प्रवृत्ति,तनाव या भय जैसे संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए। परिवार का ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां बच्चा बिना डर अपनी हर समस्या साझा कर सके।

समाज के लिए भी बड़ा संदेश-यह घटना समाज को भी यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम छोटी-छोटी गलतियों या आरोपों को संभालने में संवेदनशील हैं? क्या किसी किशोर के आत्मसम्मान और मानसिक स्थिति का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है? यदि किसी नाबालिग पर कोई आरोप हो तो कानून के अनुसार प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है। किसी भी प्रकार का सामाजिक या मानसिक दबाव भविष्य में गंभीर परिणाम दे सकता है।

क्या पुलिस को पहले से थी जानकारी?

मामले का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि एफआईआर में दावा किया गया है कि पुलिस को घटना की जानकारी पहले ही हो चुकी थी,शिकायतकर्ता के अनुसार पुलिस लाइन में पदस्थ एक आरक्षक दुकान भी पहुंचे थे और दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी हुई थी, यदि जांच में यह तथ्य सही पाया जाता है,तो यह भी जांच का विषय होगा कि उस समय नाबालिग की सुरक्षा और मानसिक स्थिति को लेकर क्या कदम उठाए गए, इसी कारण अब पुलिस की भूमिका भी जांच के केंद्र में है।

अगले दिन घर में फांसी लगाकर दी जान

एफआईआर के अनुसार 8 जुलाई 2026 की दोपहर लगभग 1:30 बजे नाबालिग किशोरी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली,परिजनों का आरोप है कि दुकान में हुई कथित प्रताड़ना,सामाजिक अपमान और मानसिक दबाव के कारण उसने यह कदम उठाया,पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 296, 107, 308(2),309(4) तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है, आगे की कार्रवाई विवेचना और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी।

दुकान संचालकों की भूमिका भी जांच के घेरे में...

यदि किसी व्यक्ति पर चोरी का संदेह होता है तो उसकी जांच करना पुलिस का अधिकार क्षेत्र है,किसी नाबालिग को लंबे समय तक बैठाकर रखना,कथित रूप से दबाव बनाना या आर्थिक मांग करना यदि जांच में सिद्ध होता है तो यह गंभीर कानूनी विषय हो सकता है, यही कारण है कि अब पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है।

पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठे प्रश्न

एफआईआर में लगाए गए आरोपों के बाद यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि यदि पुलिस को पहले से मामले की जानकारी थी,तो क्या समय रहते संवेदनशील हस्तक्षेप किया जा सकता था? हालांकि,इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

निगरानी नहीं, संवाद की जरूरत-

अभिभावकों को बच्चों की दिनचर्या,मित्रों,मानसिक स्थिति और व्यवहार पर संवेदनशील नजर रखनी चाहिए, केवल नियंत्रण नहीं, बल्कि विश्वास, संवाद और भावनात्मक सहयोग सबसे बड़ी जरूरत है, बच्चों को यह भरोसा होना चाहिए कि जीवन में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसका समाधान न हो।

निष्पक्ष जांच की मांग...

- नाबालिग के साथ दुकान में वास्तव में क्या हुआ?
- क्या कथित रूप से धन की मांग की गई?
- क्या मानसिक प्रताड़ना दी गई?
- पुलिस को कब जानकारी मिली?
- यदि जानकारी थी तो क्या कार्रवाई की गई?
- आत्महत्या तक पहुंचने वाली परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है?

अब जांच पर टिकी हैं निगाहें...

यह मामला केवल एक आपराधिक प्रकरण नहीं,बल्कि समाज,परिवार और व्यवस्था—तीनों के लिए गंभीर आत्ममंथन का विषय बन चुका है, पुलिस विवेचना से ही यह स्पष्ट होगा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप कितने सही हैं और इस दुखद घटना के लिए किन परिस्थितियां और किन लोगों की जिम्मेदारी बनती है,एक 17 वर्षीय किशोरी की मौत ने यह संदेश अवश्य दिया है कि बच्चों को केवल पढ़ाना ही पर्याप्त नहीं,बल्कि उन्हें मानसिक रूप से मजबूत, संवादशील और जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करना भी परिवार,समाज और संस्थाओं की साझा जिम्मेदारी है।

120 शीशी ऑनरेक्स कफ सिरप तस्करी मामले में बड़ा फैसला, दो आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास,1.50 लाख का अर्थदंड

एनडीपीएस एक्ट के तहत विशेष न्यायालय बैकुंठपुर का फैसला,नशे के खिलाफ सख्त संदेश

कोरिया,09 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) बैकुंठपुर ने नशीले कफ सिरप की तस्करी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक पर 1 लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है, न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों की अवैध तस्करी समाज,विशेषकर युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है और ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है,प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, माननीय विशेष न्यायाधीश आशीष पाठक ने विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 06/2025 में यह फैसला सुनाया।

120 शीशी ऑनरेक्स कफ सिरप के साथ पकड़े गए थे आरोपी

अभियोजन के अनुसार,21 नवंबर 2024 को थाना जनकपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अनवर अली उर्फ पप्पू खान एवं अजय सिंह बघेल मध्यप्रदेश के ग्राम दरदी, जिला सीधी से जनकपुर की ओर 120 शीशी ऑनरेक्स कफ सिरप बिक्री के उद्देश्य से लेकर आ रहे हैं,सूचना के आधार पर जनकपुर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को मोटरसाइकिल सहित मौके पर गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त किया। इसके बाद थाना जनकपुर में अपराध क्रमांक 277/2024 दर्ज कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

न्यायालय ने माना दोषी...

सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) के अपराध में दोषसिद्ध पाया,न्यायालय ने दोनों आरोपियों को,10-10 वर्ष का कठोर कारावास, प्रत्येक पर 1,50,000 का अर्थदंड की सजा सुनाई।

नशा तस्करों के लिए सख्त संदेश...

इस निर्णय को नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है,न्यायालय का यह फैसला दर्शाता है कि प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा, वहीं पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी कार्रवाई के चलते इस मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सकी,यह निर्णय जिले में नशा तस्करी पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है तथा युवाओं को नशे से बचाने के लिए कानून की सख्ती का स्पष्ट संकेत भी देता है।

युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता...

निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया कि किशोरों एवं युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति सामाजिक बुराइयों को जन्म देती है तथा अनेक परिवारों को बर्बादी की ओर धकेलती है, ऐसे में नशीले पदार्थों की तस्करी पर कठोर कार्रवाई समाजहित में आवश्यक है।

नौगई हत्याकांड के बाद बड़ा प्रशासनिक बदलाव,सोनहत थाना प्रभारी का हुआ तबादला

नक्सल क्षेत्र भेजे गए सोनहत के थाना प्रभारी,नौगई हत्याकांड के बाद तबादला बना चर्चा का विषय

सरकार बोली नक्सलवाद अंतिम दौर में...सोनहत के निरीक्षक पहुंचे नारायणपुर,तबादले पर उठी नई चर्चा

क्या अब निष्पक्ष होगी नौगई हत्याकांड की विवेचना? सोनहत थाना प्रभारी के तबादले से बढ़ीं उम्मीदें

रवि सिंह

कोरिया,09 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निरीक्षकों की तबादला सूची में राज्यभर के 64 निरीक्षकों के स्थानांतरण किए गए हैं,इस सूची में कोरिया जिले के सोनहत थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद पासवान का स्थानांतरण नक्सल प्रभावित जिले नारायणपुर किया गया है। राज्यभर में जारी इस स्थानांतरण आदेश को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया माना जा रहा है,लेकिन कोरिया जिले में सोनहत थाना प्रभारी के तबादले ने अलग ही चर्चा छेड़ दी है,इसकी वजह हाल के महीनों में पूरे प्रदेश में सुर्खियों में रहा नौगई तिहरा हत्याकांड है, इस मामले के बाद पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई,घटनास्थल के प्रबंधन और विवेचना को लेकर लगातार सवाल उठते रहे थे, ऐसे में तबादले को कई लोग केवल एक नियमित प्रशासनिक आदेश नहीं,बल्कि एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देख रहे हैं।

समतल जिलों से नक्सल क्षेत्रों की ओर भेजे गए निरीक्षक

तबादला सूची पर नजर डालें तो बड़ी संख्या में निरीक्षकों को बस्तर,दंतेवाड़ा,सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर जैसे जिलों में भेजा गया है, ये जिले वर्षों तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचाने जाते रहे हैं,हालांकि राज्य सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अंतिम चरण में है और सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से नक्सल गतिविधियां काफी कमजोर हुई हैं, यदि सरकार के इस दावे को आधार माना जाए,तो इन जिलों में स्थानांतरित किए गए अधिकारियों के लिए यह नई चुनौती अवश्य होगी, लेकिन भय का विषय नहीं होना चाहिए,पुलिस सेवा का मूल उद्देश्य ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

सोनहत का तबादला सबसे अधिक चर्चा में-

पूरी सूची में सबसे अधिक जिस नाम की चर्चा कोरिया जिले में हो रही है, वह है सोनहत थाना प्रभारी विनोद पासवान का, उनका स्थानांतरण नारायणपुर किया गया है, सोनहत वही थाना क्षेत्र है जहां नौगई तिहरे हत्याकांड जैसी चर्चित घटना हुई थी, घटना के बाद स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए थे, आरोप लगाए गए कि प्रारंभिक स्तर पर पुलिस अपेक्षित तत्परता नहीं दिखा सकी और विवेचना की दिशा को लेकर भी लगातार बहस होती रही, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि किसी सक्षम न्यायिक या विभागीय जांच द्वारा नहीं हुई है, लेकिन जनचर्चा और विरोध प्रदर्शनों में यह मुद्दा लगातार उठता रहा।

पीड़ित परिवार को नई उम्मीद-

सोनहत थाना प्रभारी के स्थानांतरण के बाद पीड़ित परिवार और उनके समर्थकों के बीच यह उम्मीद जगी है कि अब विवेचना आगे अधिक पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ सकेगी,कई लोगों का मानना है कि किसी संवेदनशील मामले में जांच की निष्पक्षता उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी अपराधियों की गिरफ्तारी, ऐसे मामलों में यदि जांच एजेंसी या जांच अधिकारी बदलता है तो कई बार पीड़ित पक्ष का भरोसा भी मजबूत होता है,हालांकि यह भी स्पष्ट है कि केवल किसी अधिकारी के स्थानांतरण से जांच की दिशा स्वतः नहीं बदल जाती,जांच कानून, साक्ष्य और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही आगे बढ़ती है।

तबादला दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं- कानूनी दृष्टि से किसी अधिकारी का स्थानांतरण किसी भी प्रकार से उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं माना जा सकता,प्रशासनिक तबादले शासन की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं और कई बार कार्यकाल पूर्ण होने अथवा प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर भी किए जाते हैं, इसलिए सोनहत थाना प्रभारी के स्थानांतरण को किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई या दोष सिद्ध होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

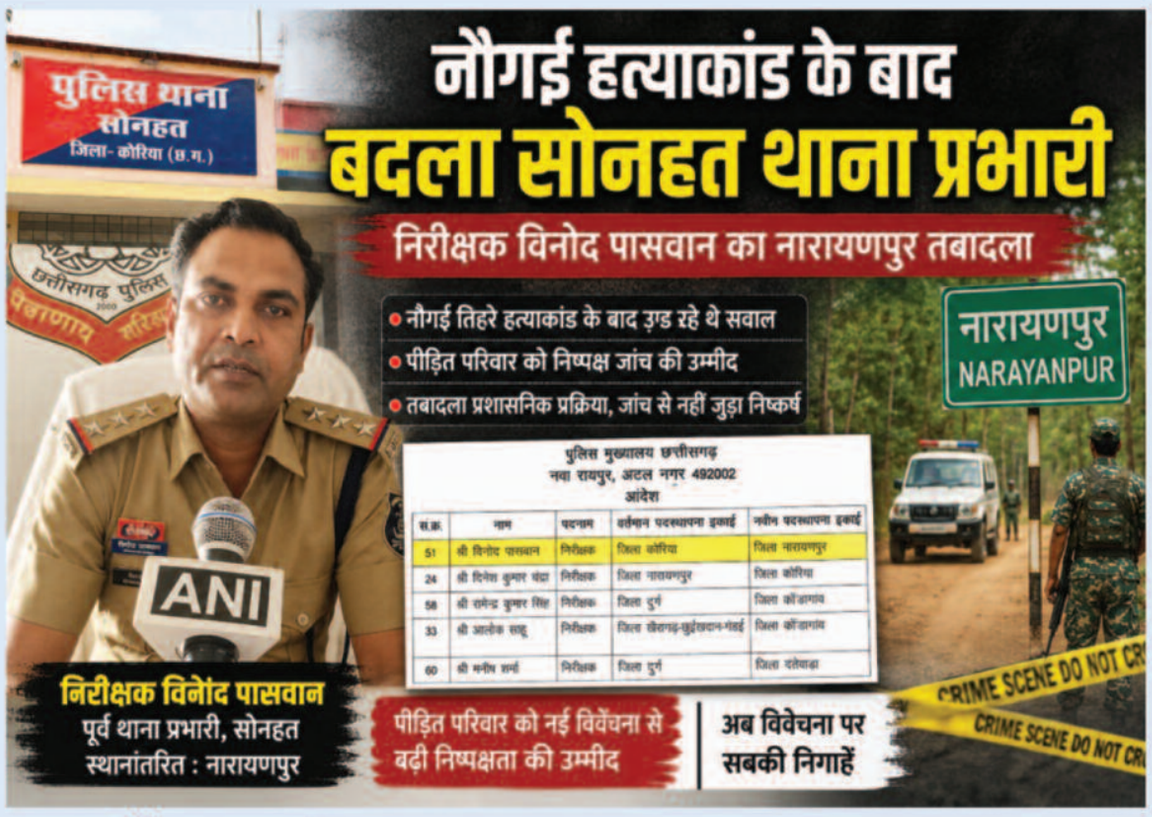

अब विवेचना पर रहेगी नजर

नौगई हत्याकांड पहले ही प्रदेश की सबसे चर्चित आपराधिक घटनाओं में शामिल हो चुका है, इस मामले में आगे की विवेचना, आरोप-पत्र,न्यायालयीन प्रक्रिया और अभियोजन की मजबूती पर लोगों की नजर बनी रहेगी,पीड़ित परिवार की अपेक्षा है कि अब जांच पूरी तरह साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़े और किसी भी स्तर पर निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न न लगे।

सरकार के दावे की भी होगी परीक्षा

एक ओर सरकार लगातार नक्सलवाद के कमजोर पड़ने का दावा कर रही है,वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में निरीक्षकों को बस्तर संभाग और अन्य नक्सल प्रभावित जिलों में भेजा गया है,ऐसे में यह तबादला सूची सरकार के दावों की भी एक तरह से परीक्षा मानी जा सकती है,यदि वास्तव में नक्सल गतिविधियां नियंत्रित हैं तो इन जिलों में कार्यभार संभालने वाले अधिकारियों के लिए बेहतर पुलिसिंग और विकासोन्मुख कानून-व्यवस्था स्थापित करने का अवसर होगा।

जनता की अपेक्षा–निष्पक्ष पुलिसिंग

कोरिया जिले के लोगों की सबसे बड़ी अपेक्षा यही है कि नौगई हत्याकांड जैसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया बिना किसी दबाव के आगे बढ़े,पुलिस अधिकारियों का आना-जाना प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है,लेकिन जनता का विश्वास तभी मजबूत होगा जब विवेचना निष्पक्ष,पारदर्शी और समयबद्ध होगी, सोनहत थाना प्रभारी का स्थानांतरण फिलहाल एक प्रशासनिक आदेश है,लेकिन इसने जिले में यह चर्चा अवश्य तेज कर दी है कि क्या अब बहुचर्चित नौगई हत्याकांड की जांच नए सिरे से अधिक भरोसेमंद तरीके से आगे बढ़ पाएगी,इसका उत्तर आने वाले समय में विवेचना की दिशा और न्यायिक प्रक्रिया ही देगी।

संयुक्त संवेदना समिति ने निभाया मानवीय दायित्व दिवंगत शिक्षिका के परिजनों को सौंपा 1 लाख का सहयोग

अब तक 33 दिवंगत सदस्यों के परिवारों को 33 लाख की सहायता,10 जुलाई तक सदस्यता अभियान जारी

-संवाददाता-

सूरजपुर,09 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। संयुक्त संवेदना समिति,सूरजपुर ने एक बार फिर अपने मानवीय दायित्व का निर्वहन करते हुए दिवंगत शिक्षिका स्व. श्रीमती ललिता सिदार के परिजनों को समिति के नियमानुसार 1 लाख की संवेदना सहायता राशि प्रदान की, समिति की ओर से यह अब तक का 33वां संवेदना सहयोग है, इसके साथ ही समिति द्वारा अब तक 33 दिवंगत सदस्यों के परिवारों को कुल 33 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है।

स्व. ललिता सिदार विकासखंड ओड़गी के पूर्व माध्यमिक शाला गुर्दापारा (संकुल केंद्र खर्रा) में शिक्षिका के रूप में पदस्थ थीं। गत 15 जून 2026 को मनेंद्रगढ़-कोटाडोल मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गई थीं, उन्हें उपचार के लिए बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया, वे मूलतः रायगढ़ जिले की निवासी थीं तथा उनका विवाह 10 मई 2026 को हुआ था।

कम उम्र में शिक्षा जगत ने खोई समर्पित शिक्षिका-महज 30 वर्ष 7 दिन की आयु और 2 वर्ष 7 माह 2 दिन के शिक्षकीय सेवाकाल में स्व. ललिता सिदार ने अपनी नवाचारी शिक्षण शैली, अनुशासन और विद्यार्थियों के प्रति समर्पण से अलग पहचान बनाई थी, उनके असामयिक निधन से शिक्षा जगत को अपूरणीय क्षति पहुंची है।

परिजनों को सौंपा गया सहायता राशि का चेक

संयुक्त संवेदना समिति की ओर से दिवंगत शिक्षिका के पिता कपूर सिंह सिदार एवं भाई गजेन्द्र सिदार को 1 लाख का चेक सौंपा गया,इस दौरान उपस्थित सभी शिक्षकों एवं समिति सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।

शीघ्र स्वत्व भुगतान का आश्वासन

कार्यक्रम में संकुल प्राचार्य प्रदीप कुमार सिंह एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी मोतीलाल राजवाड़े ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि दिवंगत शिक्षिका के समस्त सेवा संबंधी स्वत्वों का भुगतान यथाशीघ्र सुनिश्चित कराया जाएगा।

10 जुलाई तक सदस्यता अभियान-समिति के जिला संचालक सचिन त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2026 की सदस्यता प्रक्रिया जारी है तथा 10 जुलाई सदस्यता ग्रहण करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, उन्होंने सभी शिक्षक साथियों से इस सहयोगात्मक एवं मानवीय अभियान से जुड़ने का आग्रह करते हुए कहा कि यह समिति विपरीत परिस्थितियों में शिक्षक परिवारों के लिए संबल का कार्य कर रही है।

बड़ी संख्या में शिक्षक रहे उपस्थित-संवेदना राशि वितरण कार्यक्रम में समिति के ब्लॉक संचालक मो. महमूद, प्रदीप कुमार सिंह, मोतीलाल राजवाड़े, कुंजलाल यादव, भोरेलाल यादव, संजयदेव पाण्डेय, हरिनारायण दुबे, प्रिमा सिंदे, अनुपा कुशवाहा, लक्ष्मी गुप्ता, संतरा पण्डो, लक्ष्मण यादव, बालकरण यादव, राजेश पाल, शंकर सिंह नेताम, बिनोद गुप्ता, इंद्रप्रसाद सिंह, राजेश सिंह, राजेश्वर सिंह, राजेन्द्र पटेल, आनन्द कुमार, विलियम बिजू लकड़ा, शत्रुघ्न कुमार, संतोष पैकरा, अभिषेक यादव, रामगोविन्द पण्डो, गौतम नेताम सहित बड़ी संख्या में शिक्षक एवं संयुक्त संवेदना समिति के सदस्य उपस्थित रहे, संयुक्त संवेदना समिति की यह पहल न केवल आर्थिक सहयोग का माध्यम बन रही है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में शिक्षक परिवारों के साथ खड़े रहने की सामाजिक संवेदनशीलता का भी सशक्त उदाहरण प्रस्तुत कर रही है।

सड़क हादसे में घायल युवक के लिए देवदूत बने शिक्षक,समय पर उपचार से बची जान

वन विभाग कार्यालय के सामने पिकअप और बाइक की भिड़ंत,शिक्षक की तत्परता और स्वास्थ्यकर्मियों की सक्रियता से टला बड़ा हादसा

-संवाददाता-

पटना/कोरिया,09 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। नगर पंचायत पटना में सोमवार सुबह हुए सड़क हादसे में एक शिक्षक की संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय ने एक घायल युवक की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वन विभाग कार्यालय के सामने हुई इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव पर तत्काल नियंत्रण पाया जा सका।

जानकारी के अनुसार,सुबह लगभग 9 बजे वन विभाग कार्यालय के सामने एक पिकअप वाहन के बैक करने के दौरान बाइक से जोरदार टक्कर हो गई, दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर में गंभीर चोट आई और शरीर के कई हिस्सों से लगातार खून बहने लगा, इसी दौरान अपनी ड्यूटी पर जा रहे छिंदिया निवासी शिक्षक आशीष जायसवाल की नजर घायल युवक पर पड़ी,उन्होंने बिना समय गंवाए अपना वाहन रोका और आसपास मौजूद लोगों की मदद से घायल युवक को तत्काल अपने वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना पहुंचाया, अस्पताल में समय रहते इलाज शुरू होने से चिकित्सकों ने रक्तस्राव को नियंत्रित किया, जिससे युवक की जान बचाई जा सकी, सूत्रों के अनुसार घायल युवक की उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच है और वह ग्राम पंचायत बरदिया का निवासी बताया जा रहा है।

स्वास्थ्यकर्मियों ने भी निभाई अहम भूमिका- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायल युवक को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने में स्वास्थ्यकर्मी इबू खान एवं आशीष साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोनों ने प्राथमिक उपचार में तेजी दिखाते हुए घायल की स्थिति को संभाला।

पहले भी कर चुके हैं कई लोगों की मदद- स्थानीय लोगों के अनुसार, यह पहला अवसर नहीं है जब शिक्षक आशीष जायसवाल ने किसी दुर्घटना पीड़ित की मदद की हो, इससे पहले भी वे कई सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दे चुके हैं, आशीष जायसवाल का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को 'गोल्डन ऑवर' के भीतर उपचार मिल जाए तो 50 से 60 प्रतिशत तक लोगों की जान बचाई जा सकती है, उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि दुर्घटना देखने पर केवल तमाशबीन न बनें, बल्कि मानवता का परिचय देते हुए घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने में सहयोग करें, इस घटना ने एक बार फिर यह साबित किया कि समय पर मिली मदद और संवेदनशील नागरिकों की तत्परता किसी की जिंदगी बचा सकती है।

पुलिस परिवार की बेटी को न्याय दिलाने सड़क पर उतरे पुलिसकर्मी,पूर्व विधायक गुलाब कमरो बोले...एफआईआर के बाद भी गिरफ्तारी नहीं,आखिर क्यों?

पूजा पैकरा प्रकरण में निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई की मांग, कानून-व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

-संवाददाता-

कोरिया,09 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले की आदिवासी छात्रा आत्महत्या से जुड़े मामले में न्याय की मांग अब और तेज हो गई है,गुरुवार को पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पुलिस परिवार स्वयं सड़कों पर उतर आया,बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के परिजनों और स्थानीय नागरिकों ने प्रदर्शन कर नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी तथा निष्पक्ष जांच की मांग की, प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना कई सवाल खड़े करता है, उनका कहना है कि यदि कानून के अनुसार अपराध दर्ज हो चुका है,तो कार्रवाई में अनावश्यक देरी क्यों हो रही है।

पुलिस परिवार ने जताई नाराजगी- प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि न्याय में देरी से आम जनता का कानून व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होता है,उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह मामला केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज की बेटियों की सुरक्षा और न्याय से जुड़ा विषय है,इसलिए दोषियों के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

निष्पक्ष जांच की मांग-प्रदर्शन के दौरान पुलिस परिवार एवं स्थानीय नागरिकों ने एक स्वर में मांग की कि मामले की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए,सभी तथ्यों को सामने लाया जाए तथा कानून के अनुसार दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए,ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहे।

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने उठाए सवाल...

प्रदर्शन के दौरान पहुंचे पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की, उन्होंने कहा कि जब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है,तब भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना बेहद गंभीर विषय है,उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करते हुए दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार शीघ्र एवं कठोर कार्रवाई करने की मांग की,गुलाब कमरो ने कहा कि यदि समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिसकर्मी का अपना परिवार ही न्याय के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाए, तो यह कानून-व्यवस्था के लिए चिंताजनक संकेत है,उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति आम नागरिकों के मन में भी सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को लेकर सवाल पैदा करती है।

बाघ की दहाड़... नंदी की शक्ति, द वीवन की रिलीज डेट का एलान

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया अभिनीत फिल्म द वीवन की रिलीज डेट 25 सितंबर 2026 घोषित हो गई है।

एक्शन,ड्रामा, रोमांस और सस्पेंस-थ्रिलर के बाद अब कुछ नई कहानियां बड़े पर्दे पर आ रही हैं। नाग-नागिन से लेकर स्त्री-भेड़िया जैसी कहानियां दर्शकों के सामने आ रही हैं। अब जल्द ही एक और फिल्म सामने आ रही है,जिसमें रोमांस से लेकर डर और ड्रामा सबकुछ होगा। फिल्म का नाम है वन और अब लीजिए फिल्म की रिलीज डेट का एलान हो गया है।

द वीवन की रिलीज डेट का एलान

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की मचअवेटेड फिल्म वन को लेकर चर्चा काफी वक्त से हो रही है। अब लीजिए हाल ही में मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का एलान कर दिया है। इसके अलावा फिल्म का एक पोस्टर भी रिलीज किया गया है।

फिल्म के नए पोस्टर के मुताबिक,फिल्म अब 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई है। पोस्टर में एक ताकतवर योद्धा जैसे किरदार को एक बैल और एक बाघ के बीच खड़े हुए देखा जा सकता है। पोस्टर दमदार होने के साथ-साथ काफी रहस्यमयी भी लग रहा है। पोस्टर फिल्म की कहानी को लेकर उत्सुकता बढ़ा रहा है।

क्या है फिल्म वन की कहानी?

द वन की कहानी असल में बेहद हटकर होने वाली है। फिल्म की कहानी भारतीय लोककथाओं से प्रेरित बताई जा रही है, जिसमें फैंटेसी, एक्शन,कॉमेडी और एडवेंचर का शानदार मेल देखने को मिलेगा। फिल्म में एक नई दुनिया,शानदार विजुअल्स और बड़े पर्दे का एक अलग अनुभव देखने को मिलेगा। फिल्म का मकसद ऐसी भारतीय कहानी को सामने लाना है, जिनसे हर उम्र के दर्शक जुड़ सकें। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि अपने किरदारों और कहानियों के साथ एक नई दुनिया की शुरुआत है। मेकर्स पहले ही द लीजेंड ऑफ वन कॉमिक बुक के जरिए इस दुनिया की पहली झलक दिखा चुके हैं।फिल्म बालाजी मोशन पिक्चर्स और टीवीएफ मोशन पिक्चर्स मिलकर साथ बना रहे हैं। फिल्म को दीपक कुमार मिश्रा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी अरुणाभ कुमार ने लिखी है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया के अलावा कई और किरदार भी नजर आएंगे। द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट के टाइटल के साथ फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

गोलमाल 5 से जुड़ा अभिनेत्री प्रियामणि का नाम, खलनायिका बनकर मचाएगी धमाल

रोहित शेट्टी एक बार फिर गोलमाल फ्रैंचाइजी की दुनिया में कदम रख चुके हैं। इस सुपरहिट फिल्म की 5वीं किस्त के साथ अजय देवगन और उनकी पूरी पलटन लौटने के लिए तैयार है। काफी समय से चर्चा थी कि इस बार निर्माता फिल्म में महिला अभिनेत्री को शामिल नहीं करेंगे और यह पूरी तरह से पुरुष प्रधान फिल्म होगी। अब फिल्म पर आई हालिया जानकारी पिछले दावे से पूरी तरह उलट है, क्योंकि एक अभिनेत्री इसमें शामिल हो गई हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, गोलमाल 5 से अभिनेत्री प्रियामणि का नाम जुड़ चुका है। फैमिली मैन और आर्टिकल 370 जैसी फिल्मों व सीरीज से चर्चा बटोरने वालीं अभिनेत्री फिल्म में एक नकारात्मक किरदार निभाती हुई दिखाई देंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि रोहित दर्शकों का मनोरंजन बढ़ाने के लिए अपनी फिल्म में अभिनेत्री का नकारात्मक किरदार किस तरह से दर्शाते हैं। फिलहाल तो प्रियामणि के जुड़ने की खबरों ने ही फैंस को उत्साहित कर दिया है।

गोलमाल 5 में अजय के अलावा, अरशद वारसी,श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, कुणाल खेमू और शरमन जोशी भी अपने-अपने किरदारों में वापसी करते हुए दिखाई देंगे। दिलचस्प बात यह है कि अक्षय कुमार भी फिल्म का आधिकारिक हिस्सा बन चुके हैं। कुछ महीने पहले निर्माताओं ने एक पोस्टर जारी करते हुए फिल्म की पूरी स्टारकास्ट से रूबरू करवाया था। खबरों के मुताबिक, फिल्म को 2027 की शुरुआत में रिलीज करने की योजना बनाई जा रही हैं।

खेसारी विवाद के बीच अंजना सिंह का नया अंदाज

भोजपुरी सिनेमा की चर्चित एक्ट्रेस अंजना सिंह एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं। उनकी एक नई इंस्टाग्राम रील तेजी से वायरल हो रही है,जिसे फैंस खेसारी लाल यादव से जुड़े विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि,अंजना सिंह ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है,लेकिन कैप्शन में लिखी गई लाइन अकेले काफी हूं ने सोशल मीडिया पर चर्चाओं को हवा दे दी है।

अंजना सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस रील में वह कार में बैठी नजर आ रही हैं और उनके चेहरे पर गंभीर भाव दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में एक डायलॉग सुनाई देता है, जिसमें अकेले लड़ने और हार न मानने की बात कही गई है। इसी के साथ अंजना ने कैप्शन लिखा, अकेले काफी हूं। इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे उनके हालिया विवाद से जोड़ना शुरू कर दिया। कई लोगों का मानना है कि यह रील खेसारी लाल यादव विवाद के बीच उनका जवाब हो सकती है। वहीं कुछ यूजर्स ने कमेंट कर खेसारी लाल यादव का समर्थन किया, जबकि कुछ लोगों ने अंजना सिंह के पक्ष में अपनी राय रखी। दरअसल, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अंजना सिंह ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने लाइव वीडियो में किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया,लेकिन भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव को लेकर कई बातें कहीं। उन्होंने उन्हें भैया कहकर संबोधित किया और भोजपुरी गीतकार व लेखक अखिलेश कश्यप को भी टैग किया था। अंजना सिंह ने लाइव के दौरान कहा था कि उन्हें बार-बार लखनऊ बुलाकर कुछ दिखाने की बात कही जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्या दिखाना चाहते हैं, जिसे वह नहीं देख पाएंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि जिस व्यक्ति की चर्चा हो रही है,उसके बारे में पूरी इंडस्ट्री जानती है और अगर वह बोलना शुरू करेंगी तो कई बातें सामने आ सकती हैं। अपने लाइव वीडियो में अंजना सिंह ने एक पुरानी घटना का जिक्र भी किया था। उन्होंने दावा किया कि कई साल पहले बांगुर नगर स्थित एक ऑफिस में खेसारी लाल यादव एक अभिनेत्री के साथ मौजूद थे और उसी दौरान उनकी पत्नी वहां पहुंच गई थीं। हालांकि,अंजना सिंह के इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और खेसारी लाल यादव की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

वहीं,अंजना सिंह के बयान के बाद भोजपुरी गीतकार और लेखक अखिलेश कश्यप ने भी सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो शेयर किए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अपने वीडियो में चाची शब्द का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोग उनसे जवाब देने की मांग कर रहे हैं,लेकिन हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अखिलेश कश्यप ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि अगर वह कुछ बातें सार्वजनिक कर देंगे तो काफी चर्चा हो जाएगी। उनके इन बयानों के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया और सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थक आमने-सामने आ गए। फिलहाल अंजना सिंह की नई रील ने एक बार फिर इस पूरे मामले को चर्चा में ला दिया है।

युविका संग रिश्ते पर प्रिंस का बड़ा बयान, खोले जिंदगी के राज

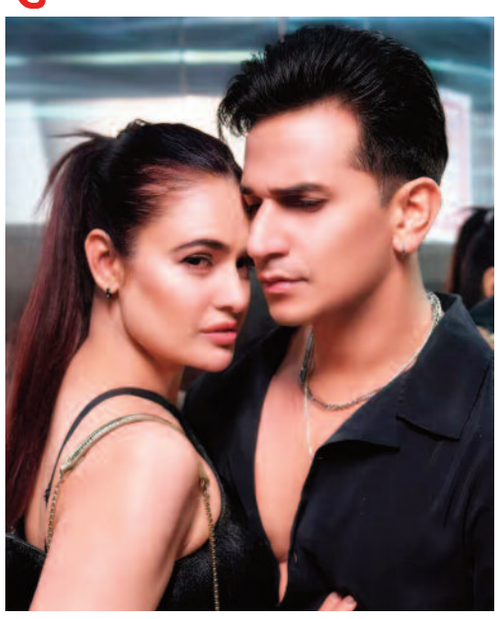

टीवी के मशहूर अभिनेता और रियलिटी शो स्टार प्रिंस नरूला इन दिनों अपनी निजी जिंदगी और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा में हैं। पत्नी युविका चौधरी के साथ रिश्ते में तनाव की खबरों के बीच अब प्रिंस ने अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि किस तरह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों ने उनकी जिंदगी को प्रभावित किया और इसका असर उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ा। प्रिंस नरूला ने हाल ही में अभिनेत्री नेहा धूपिया के शो 'डबल डेट' में अपनी हेल्थ जर्नी को लेकर कई खुलासे किए। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आया था जब उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें एक दिन में 18 टैबलेट्स तक लेनी पड़ती थीं।

प्रिंस ने कहा कि वह दौर उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था। उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि उन्हें पल्पिटेशन यानी दिल की धड़कन तेज होने की समस्या होती थी। इसके अलावा रात के समय डर महसूस होता था, वजन भी बढ़ गया था और कई अन्य मेडिकल समस्याओं से गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा कि उस समय मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की परेशानियां थीं। इस दौर ने उन्हें काफी प्रभावित किया और उनकी निजी जिंदगी पर भी इसका असर पड़ा।

शादीशुदा जिंदगी पर पड़ा असर

प्रिंस नरूला ने बताया कि जब कोई व्यक्ति खुद मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है तो उसका असर उसके आसपास के रिश्तों पर भी पड़ता है। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी स्वास्थ्य समस्याओं और तनावपूर्ण समय का असर उनकी शादी पर भी पड़ा। हालांकि,प्रिंस और युविका चौधरी ने हाल ही में अपने रिश्ते में अनबन की खबरों को गलत बताया था। दोनों ने साफ किया था कि उनके बीच सब ठीक है और सोशल मीडिया पर चल रही खबरें सही नहीं हैं। प्रिंस और युविका की मुलाकात रियलिटी शो 'बिग बॉस 9' के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। साल 2018 में दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों टीवी इंडस्ट्री के चर्चित कपल्स में शामिल रहे हैं।

प्रिंस ने साझा किया अनुभव

प्रिंस ने बातचीत में बताया कि मुश्किल समय ने उन्हें जिंदगी को नए नजरिए से देखने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और इंसान को अपने शरीर और मानसिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए।

उन्होंने यह भी बताया कि बीमारी और तनाव के दौर में परिवार और करीबी लोगों का साथ बहुत जरूरी होता है। उनके मुताबिक, ऐसे समय में रिश्तों की असली परीक्षा होती है। प्रिंस नरूला के इस खुलासे के बाद उनके फैंस उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके संघर्ष और हिम्मत की तारीफ की है। फिलहाल प्रिंस अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी सेहत पर भी ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े अनुभव साझा कर यह संदेश दिया है कि मुश्किल दौर चाहे कितना भी बड़ा हो,सही सोच और अपनों के सहयोग से उससे बाहर निकला जा सकता है।

खेल समाचार

सौरव गांगुली आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल, सचिन ने दी बधाई

नई दिल्ली,09 जुलाई 2026। आईसीसी हॉल ऑफ़ फ़ेम में शामिल होने के एक दिन बाद भी पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को बधाईयाँ मिल रही हैं। भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक गांगुली को बधाई देने वालों में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और विश्व कप विजेता ऑलराउंडर युवराज सिंह शामिल हैं। गांगुली को उनके 54वें जन्मदिन पर आआईसीसी हाल ऑफ़ फ़ेम में शामिल किया गया। वे यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले कुल मिलाकर 12वें भारतीय और 10वें भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने। गांगुली के साथ लंबे समय तक ओपनिंग पार्टनर रहे और भारतीय क्रिकेट की सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी जोड़ियों में से एक सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, जब से हम 14 साल के थे,तब से एक-दूसरे को जानते हैं, इसलिए अब बहुत कम ही चीजें हैरान करती हैं। यह भी उनमें से एक नहीं थी।

हर्ष मेहता पिकलबॉल वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय प्रो कैटेगरी की अगुवाई करेंगे

मुंबई,09 जुलाई 2026। इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन ने पिकलबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए आधिकारिक टीम इंडिया का ऐलान किया है। एक बहुत ही कड़े सिलेक्शन प्रोसेस के बाद, देश के बेहतरीन सीनियर पिकलबॉल खिलाड़ियों को पिकलबॉल वर्ल्ड कप 2026 में प्रो कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। यह टूर्नामेंट वियतनाम के दा नांग में 30 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा।

इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सूर्यवीर सिंह भुल्लर ने कहा, यह टीम भारतीय पिकलबॉल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हर्ष मेहता की शानदार लीडरशिप और अर्जुन,अनीश,अमन,आलिया,मिहिका और दमदार अमलस डीवाला बहनों जैसे बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ, हमारे पास एक वर्ल्ड-क्लास टीम है। हम दा नांग सिर्फ़ मुकाबला करने नहीं जा रहे हैं, हम जीतने जा रहे हैं। इस टीम में वर्ल्ड कप जीतने की भूख,गहराई और तालमेल है। इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन देश के अंदर और इंटर नेशनल लेवल पर भारत की पिकल बॉल में कामयाबी के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रही है और आगे भी रहेगी।

भारत-इंग्लैंड महिला टेस्ट में किसका पलड़ा भारी?

नई दिल्ली,09 जुलाई 2026। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 10 जुलाई से एक रोमांचक इकलौता टेस्ट मैच खेला जाएगा। दोनों देशों के बीच टेस्ट क्रिकेट के लंबे इतिहास को देखें तो अब तक कुल 15 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है।

आमने-सामने के आंकड़ों में भारत का दबदबा

भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच टेस्ट मैचों की कुल संख्या 15 रही है। इन मुकाबलों में भारतीय महिलाओं ने तीन मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड की टीम केवल एक ही मैच जीत पाने में सफल रही है। वहीं, 11 मुकाबले बिना किसी परिणाम के ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। दोनों टीमों के बीच टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत साल 1986 में हुई थी, जब तीन मैचों की पहली सीरीज 0-0 से ड्रॉ रही थी। इसके बाद से लेकर 2023 तक दोनों टीमों ने कई यादगार मुकाबले खेले हैं।

ऐतिहासिक प्रदर्शन और यादगार रिकॉर्ड

भारतीय टीम का इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड भी बेहद शानदार है। इन दोनों देशों के बीच टेस्ट इतिहास के टॉप 3 सर्वोच्च स्कोर भारत के ही नाम हैं। अगस्त 2002 में भारतीय टीम ने एक पारी में 467 रनों का विशाल स्कोर बनाया था। इसके बाद दिसंबर 2023 में 428 रन और जुलाई 1986 में 426/9 रनों का स्कोर बनाना भारतीय टीम की बल्लेबाजी की मजबूती को दर्शाता है। साल 2006 और 2014 के साथ-साथ हालिया दिसंबर 2023 के मैचों में भारत की जीत इस बात की गवाह है कि भारतीय खिलाड़ी इंग्लिश परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं।

विंबलडन में आर्थर फेरी का बड़ा धमाका

फ्रेंच ओपन के रनर-अप को हराकर रचा इतिहास

नई दिल्ली,09 जुलाई 2026। विंबलडन 2026 में ब्रिटेन के आर्थर फेरी ने अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फेरी ने फ्लेवियो कोबोली को सीधे सेटों में 6-4, 7-6(4), 6-0 से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही वे टूर्नामेंट के अंतिम चार में पहुंचने में सफल रहे हैं। टूर्नामेंट में वाइल्ड कार्ड के जरिए प्रवेश पाने वाले फेरी ने इतिहास रचते हुए विंबलडन के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले दूसरे वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है।

इतिहास रचकर सेमी फाइनल में फेरी का प्रवेश

विंबलडन के इतिहास में इससे पहले वर्ष 2001 में गोरान इवानिसेविच ने वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी के रूप में सेमीफाइनल में जगह बनाकर करिश्मा किया था। फेरी अब इवानिसेविच की बराबरी करते हुए इस उपलब्धि को दोहराने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अतिरिक्त,वे 'ओपन एरा' में विंबलडन सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले पांचवें ब्रिटिश पुरुष खिलाड़ी भी बने हैं। उनसे पहले इस विशिष्ट सूची में रोजर टेलर, एंडी मरे, टिम हेनमैन और कैमरून नॉरी का नाम दर्ज है। फेरी का अब तक का प्रदर्शन अत्यंत प्रभावी रहा है,जिसने दर्शकों को खासा प्रभावित किया है।

सेमीफाइनल में ज्वेरेव से होगी कड़ी टक्कर

सेमीफाइनल में आर्थर फेरी का सामना मौजूदा रोलैंड गैरोस चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ज्वेरेव ने क्वार्टर फाइनल मैच में टेलर फ्रिट्ज को 6-4, 6-4, 6-2 के सीधे सेटों में मात देकर अंतिम चार में अपनी जगह पक्की की है। ज्वेरेव के लिए यह टूर्नामेंट कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि वे अपने करियर में पहली बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। यह मुकाबला ऑल इंग्लैंड क्लब में काफी रोमांचक होने की उम्मीद है, जहां दोनों खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं।

एन्जो मारेस्का की नई टीम तैयार, मैनचेस्टर सिटी में विली कैबलेरो की वापसी

मैनचेस्टर,09 जुलाई 2026। इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर सिटी ने नए मैनेजर एन्जो मारेस्का के साथी कोचिंग स्टाफ की आधिकारिक घोषणा कर दी है। मारेस्का की इस नई टीम में सबसे बड़ा नाम क्लब के पूर्व गोलकीपर विली कैबलेरो का है, जिन्होंने कई साल बाद एक बार फिर मैनचेस्टर सिटी में वापसी की है।

क्लब ने बताया कि रॉबर्टो विटिएलो, विली कैबलेरो, डैनी वॉकर,मिशेल डी बर्नार्डिंन, मार्कोस अल्वारेज, डेनिस सिल्वा और जेवियर मोलिना, एन्जो मारेस्का की नई टीम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा सेट-पीस कोच जेम्स फ्रेंच और गोलकीपिंग कोच रिचर्ड राइट अपने मौजूदा पद पर बने रहेंगे। 43 वर्षीय एन्जो मारेस्का को पिछले महीने तीन साल के अनुबंध पर मैनचेस्टर सिटी का नया मैनेजर बनाया गया था। उनके साथ लंबे समय से काम कर रहे रॉबर्टो विटिएलो अब सहायक मैनेजर की जिम्मेदारी संभालेंगे। विटिएलो और मारेस्का का साथ खिलाड़ी के रूप में भी रहा है। दोनों ने इटली के कई क्लबों के लिए एक साथ खेला और बाद में कोचिंग में भी साथ काम किया। उन्होंने पर्मा,लीसेस्टर सिटी और चेल्सी में भी मारेस्का के साथ जिम्मेदारी निभाई।

अर्जेंटीना के पूर्व गोलकीपर विली कैबलेरो ने 2014 से 2017 के बीच मैनचेस्टर सिटी के लिए 48 मुकाबले खेले थे। वह क्लब के लिए लीग कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रहे थे और पेनल्टी शूटआउट में उनके शानदार प्रदर्शन को आज भी याद किया जाता है। खिलाड़ी के रूप में क्लब छोड़ने के बाद कैबलेरो ने मारेस्का के साथ लीसेस्टर सिटी और चेल्सी में कोचिंग स्टाफ में काम किया। अब वह फिर से एतिहाद स्टेडियम लौट आए हैं।

CMYK

छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव
अब 1 अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र
स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश...

रायपुर,09 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। आगामी शैक्षणिक सत्र 2027-28 से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र अब हर वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक संचालित होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। भौगोलिकसंदर्भ राज्य सरकार का यह निर्णय देश के अन्य प्रमुख शिक्षा बोर्डों और शिक्षा मंडलों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही वर्तमान में लागू 16 जून से 30 अप्रैल तक संचालित होने वाले शिक्षा सत्र की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी।

16 जून से शुरू होने वाला सत्र होगा समाप्त

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार,अब तक प्रदेश में स्कूलों का शैक्षणिक सत्र 16 जून से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल तक चलता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह प्रणाली पूरी तरह बदल जाएगी और प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक नियमित शैक्षणिक सत्र संचालित किया जाएगा। हालांकि,छात्रों के ग्रीष्मकालीन अवकाश में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 मई से 15 जून तक का ग्रीष्मकालीन अवकाश पहले की तरह ही जारी रहेगा।

सत्र के पहले दिन से ही शुरू होंगी सभी छात्र हितैषी योजनाएं

नई व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसी दिन से विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण, सरस्वती सायकल योजना के तहत सायकलों का वितरण, स्कूली गणवेश (यूनिफॉर्म) उपलब्ध कराने सहित सभी छात्रहितैषी योजनाओं और शैक्षणिक गतिविधियों की शुरुआत अनिवार्य रूप से की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सत्र के आरंभ से ही सभी आवश्यक सुविधाएं विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाएं,ताकि पढ़ाई किसी भी स्तर पर प्रभावित न हो। स्कूल शिक्षा विभाग का मानना है कि नए शैक्षणिक कैलेंडर से विद्यार्थियों को सत्र के पहले दिन से ही पढ़ाई के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। इससे किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य योजनाओं के वितरण में होने वाली देरी समाप्त होगी और शिक्षण कार्य समय पर शुरू हो सकेगा।

डिजिटल रजिस्ट्री में भी फर्जीवाड़े में सफल हो रहे शातिर...मृत किसान को 'पिता' बताकर जमीन हड़पने की साजिश

गरियाबंद,09 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने का दावा भले ही किया जा रहा है मगर फर्जीवाड़ा करने वालों का कारोबार अब भी बदस्तूर जारी है। गरियाबंद जिले के अमलीपदर तहसील के बजाड़ी गांव में जाली आधार कार्ड के सहारे ढाई एकड़ कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। शातिर ने मृत किसान हरिसिंह नागेश को अपना पिता बताकर जमीन बेच दी। इस बीच सरपंच की जागरूकता से नामांतरण रुक गया। अब पूरे मामले में पटवारी,गवाह और दस्तावेज तैयार करने वालों की भूमिका की जांच शुरू हो गई है।

पड़ोसी के आधार में छेड़छाड़ कर कराई रजिस्ट्री

मामला बजाड़ी के खसरा नंबर 12 की जमीन का है। 15 अप्रैल 2025 को तत्कालीन सहायक पंजीयक चितेश देवांगन की मौजूदगी में उरमाल निवासी शांति लाल जैन को यह जमीन 1.5 लाख रुपये में बेची गई। जांच में खुलासा हुआ कि रजिस्ट्री में हरिसिंह नागेश पिता लक्ष्मण के नाम पर वार्ड-2 निवासी हरिराम नागेश पिता जयमल का आधार नंबर इस्तेमाल किया गया। जमीन बेचने वाला असली शख्स भंवर लाल नागेश पिता लखन है, जो आधार धारक का पड़ोसी है। पूछताछ में भंवर ने माना कि उसने उपनाम हरिसिंह बताकर फर्जी आधार बनवाया और चेक से पैसा निकाल लिया।

2018 से रची जा रही थी साजिश

असल भूमि स्वामी देवभोग के कैठपदर निवासी 70 वर्षीय हरिसिंह नागेश की मार्च 2018 में मौत हो गई थी। भंवर लाल ने 2022 में पत्नी प्रभंजली के जरिए मैनपुर तहसील में फौती दर्ज कराने आवेदन कराया और मृतक को अपना पिता बताया। हालांकि इश्तहार के बाद यह प्रयास भी नाकाम हो गया। ग्रामीणों के अनुसार यह जमीन 80 साल से तुकाराम कुम्हार परिवार के पास थी और ग्राम देवी की सेवा के लिए दी गई थी। जब जमीन के नामांतरण के लिए फाइल ग्राम पहुंची तो सरपंच यशोदा नेताम ने विक्रेता को गांव में नहीं रहने की बात कहकर असहमति जता दी। इससे मामला खुल गया। अब देवभोग उपपंजीयक कार्यालय के प्रभारी सहायक पंजीयक अजय चंद्रवंशी जांच कर रहे हैं। प्रभारी ने बताया कि रजिस्ट्री के समय ई-केवाईसी का प्रावधान नहीं था, लेकिन फर्जी आधार बनाने, फौती दर्ज कराने, रिकॉर्ड बदलने और दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले सभी जांच के दायरे में हैं।

महादेव ऐप केस...6 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट
सौरभ चंद्राकर-रवि उप्पल के खिलाफ नए सबूत पेश,आपराधिक साजिश रचने का आरोप

रायपुर,09 जुलाई 2026। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में सीबीआई ने काली कमाई और मनी लॉन्ड्रिंग के नए सबूत पेश किए हैं। केस के आरोपी अशीम दास, रोहित गुलाटी, विकास छपारिया, अनिल धम्मानी, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा इन 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन सभी पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा महादेव सट्टा ऐप के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ भी सबूत अदालत में पेश किए गए हैं। बता दें कि सीबीआई ने अब तक 66 आरोपियों के खिलाफ 5 अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की हैं।

सौरभ चंद्राकर ओमान में गिरफ्तार

बता दें कि महादेव सट्टा ऐप का संचालक सौरभ चंद्राकर ओमान में अरेस्ट हुआ है। उस पर फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश करने का आरोप है। चंद्राकर पिछले कुछ समय से संयुक्त अरब अमीरात में रह रहा था। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, सौरभ को भारतीय एजेंसियों द्वारा जारी इंटरपोल के रेड नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने उसे वापस लाने के लिए ओमान को औपचारिक प्रत्यर्पण की तैयारियों में जुटी है। चंद्राकर को ओमान की राजधानी मस्कट स्थित हाई-सिक्योरिटी अल खौद डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। वह करीब 5000 करोड़ रुपए के बेटिंग घोटाले का आरोपी है और 2019 से फरार है।

66 आरोपियों के खिलाफ 5 चार्जशीट पेश हो चुकी

इससे पहले महादेव ऐप से जुड़े एक अन्य मामले में सीबीआई ने 66 आरोपियों के खिलाफ 5 अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की हैं। इनमें सौरभ चंद्राकर,रवि उप्पल और बेटिंग सिंडिकेट के कई सदस्य शामिल हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक,यही लोग अवैध सट्टेबाजी से कमाए गए पैसे को अलग-अलग माध्यमों से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और पूरे नेटवर्क को चलाने का काम करते थे। इन मामलों में आरोपियों पर आईपीसी और छत्तीसगढ़ गैंबलिंग प्रोहिबिशन एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं।

देशभर में फैला ऑनलाइन बेटिंग का नेटवर्क : सीबीआई ने बताया कि महादेव ऐप देश में पकड़े गए सबसे बड़े गैर-कानूनी बेटिंग सिंडिकेट में से एक है, जिसे भारत के बाहर से चलाया जाता है। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों यूजर्स तक पहुंचने वाला एक देशव्यापी नेटवर्क बनाया। जांच से पता चला है कि यह सिंडिकेट पूरे देश में गैर-कानूनी बेटिंग पैनल चलाता था,यूजर्स को एनरोल करता था और गेम्स और बेटिंग मार्केट चलाता था। इससे गैर-कानूनी प्रॉफिट कमाता था, जिसे फिर म्यूल अकाउंट्स के जाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता था और आखिर में फंड विदेश में ट्रांसफर कर दिया जाता था। क्राइम से हुई कमाई का कुछ हिस्सा सरकारी कर्मचारियों को प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिया जाता था।

मुख्य आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस : जांच से पता चला कि महादेव ऐप के प्रमोटर और उनके कई साथी कुछ साल पहले वेस्ट एशिया के देशों में भाग गए थे और भारत के बाहर से इस नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने बताया कि विदेश भाग चुके 4 मुख्य आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है।

17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू की रिमांड में रहेंगे रामगोपाल अग्रवाल....

रायपुर,09 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब, कोल लेवी और कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी रामगोपाल अग्रवाल ने 3 साल बाद सरेंडर किया। रामगोपाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष थे। उन पर घोटाले का पैसा राजीव भवन मंगवाने का आरोप है। उन्होंने रायपुर स्थित आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) के दफ्तर पहुंचकर सरेंडर किया। गुरुवार को ईओडब्ल्यू ने मेडिकल जांच के बाद अग्रवाल को रायपुर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू की कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान ईओडब्ल्यू की टीम उनसे मामले में पूछताछ करेगी। बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि ईओडब्ल्यू ने 14 दिन कि रिमांड मांगी थी, लेकिन दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 9 दिन की कस्टोडियल रिमांड दी है। वहीं, कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इसके विरोध में कांग्रेस कल पूरे प्रदेशभर में प्रदर्शन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कोर्ट पहुंचे थे।

घोटाले का पैसा राजीव भवन मंगवाने का आरोप : मामला कोयला लेवी घोटाले की जांच से जुड़ा है। जांच के दौरान सूर्यकांत तिवारी की जब्त डायरी में कांग्रेस भवन के नाम पर करोड़ों रुपए की एंट्री मिली है। ईओडब्ल्यू का दावा है कि यह रकम रामगोपाल अग्रवाल के जरिए कांग्रेस भवन तक पहुंची थी। पैसे कहां से आए, किसने पहुंचाए,किसने लिए और उनका इस्तेमाल कहां हुआ,इन सभी बिंदुओं पर पूछताछ जारी है। वहीं, ईओडब्ल्यू ने उनके बेटे वैभव अग्रवाल से भी 2 दिनों तक लंबी पूछताछ की है। ईओडब्ल्यू का दावा है कि शराब घोटाला केस में अनवर ढेबर और उसके लोगों ने करोड़ों रुपए कांग्रेस भवन में रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाए। इसके अलावा कस्टम मिलिंग केस में भी रोशन चंद्राकर ने करोड़ों रुपए कांग्रेस भवन में रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाए।

वित्तीय लेन-देन की जांच जारी : ईओडब्ल्यू रामगोपाल अग्रवाल की भूमिका, संबंधित व्यक्तियों से संपर्क,वित्तीय लेन-देन, धन के स्रोत,प्राप्ति और उपयोग की जांच कर रही है। एजेंसी का कहना है कि पूछताछ जब्त डायरी, दस्तावेजों,डिजिटल साक्ष्यों और विवेचना के दौरान जुटाई गई अन्य सामग्री के आधार पर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक,बेटे से पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने रामगोपाल अग्रवाल के पिछले 3 सालों के ठिकानों,आर्थिक लेन-देन और कथित नेटवर्क से जुड़े कई सवाल किए है। एजेंसी का कहना है कि जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रामगोपाल अग्रवाल का नाम करीब 3 हजार करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले,450 करोड़ रुपए के कोल लेवी वसूली मामले और 127 करोड़ रुपए के कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन घोटाले की जांच में सामने आया है।

भिलाई के होटल में म्यूजिक आर्टिस्ट की संदिग्ध मौत,परिवार ने लगाया हत्या का गंभीर आरोप

भिलाई,09 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के भिलाई से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ 19 वर्षीय म्यूजिक आर्टिस्ट शादाब की एक होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शादाब,जो पियानो बजाने में माहिर था और जवाहर नगर का रहने वाला था,मंगलवार शाम को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल पहुंचा था। अगले दिन सुबह जब उसके दोस्त और परिजन होटल पहुंचे, तो उन्हें शादाब का शव बिस्तर पर मिला,जबकि पंखे से एक स्कार्फ का फंदा लटका हुआ था। इस घटना ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि मृतक के परिजनों ने युवती पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। शादाब के भाई अल्ताफ शेख और अन्य परिजनों ने पुलिस द्वारा इसे आत्महत्या माने जाने की संभावना पर कड़ा विरोध जताया है। परिजनों का आरोप है कि युवती ने पहले शादाब को बेल्ट से बुरी तरह पीटा और उसके बाद ब्लेड से स्वयं के हाथ और गर्दन काटकर उसे धमकाया। परिजनों का दावा है कि शादाब की हत्या करने के बाद युवती पूरी रात उसके शव के साथ कमरे में ही मौजूद रही। सीसीटीवी फुटेज में भी युवती को सुबह 6 बजे कमरे से बाहर निकलते और फिर वापस अंदर जाते हुए देखा गया है। परिजनों का कहना है कि जिस हालत में शव मिला है,उसे देखकर यह किसी भी हाल में आत्महत्या नहीं लगती। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। दोस्तों के अनुसार,शादाब का अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका था और उसने उसे हर जगह से ब्लॉक भी कर दिया था। घटना वाले दिन वह अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ होटल में डेट पर था। सूत्रों की मानें तो उसी दौरान शादाब की एक्स-गर्लफ्रेंड का कॉल आया, जिसे लेकर उनकी नई गर्लफ्रेंड नाराज हो गई।

छत्तीसगढ़ में विदेशी पेड़ 'कोनोकार्पस' के रोपण पर पूर्ण प्रतिबंध,अब नहीं लगेगा एक भी नया पौधा

रायपुर,09 जुलाई 2026। पर्यावरण संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूरे राज्य में विदेशी और आक्रामक प्रजाति कोनोकार्पस के नए पौधे लगाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने 6 जुलाई को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-5 के तहत आदेश जारी किया है। सरकार के आदेश के अनुसार अब राज्य की सीमा में कोई भी व्यक्ति,सरकारी विभाग, नगर निगम, पंचायत,सार्वजनिक उपक्रम,स्वायत्त संस्था या निजी एजेंसी कोनोकार्पस का नया वृक्षारोपण नहीं कर सकेगी। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कोनोकार्पस मूल रूप से विदेशी तटीय प्रजाति है, जो तेजी से बढ़ती है। इसे कई राज्यों में सड़क किनारे सजावटी पेड़ के रूप में लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय सशक्त समिति की 21 अगस्त 2025 की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने यह कदम उठाया। स्थानीय वनस्पतियों और जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकती है।

प्राकृतिक पारिस्थितिकी को असंतुलित कर सकती है। समिति ने नए रोपण पर रोक के साथ-साथ पहले से लगे पौधों को चरणबद्ध तरीके से देशी प्रजातियों से बदलने की भी सिफारिश की थी।

छत्तीसगढ़ में 5 आईएएस अधिकारियों का तबादला
जीपीएम को मिला नया-कलेक्टर...विजय दयाराम को मिली जिम्मेदारी

रायपुर,09 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। इस फेरबदल में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले को नया कलेक्टर मिला है। वहीं स्कूल शिक्षा,तकनीकी शिक्षा, शहरी विकास और जिला पंचायत महासमुंद में भी नई नियुक्तियां की गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के कलेक्टर संतोष कुमार देवांगन (आईएएस-2013) को उनके वर्तमान पद से हटाकर विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग बनाया गया है। जबकि विजय दयाराम के (आईएएस-2015) को जीपीएम का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे संचालक,तकनीकी शिक्षा, रोजगार-प्रशिक्षण और छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास अभिकरण का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।

हेमंत नंदनवार को तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी : हेमंत रमेश नंदनवार (आईएएस-2020) को संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

सुमित अग्रवाल (आईएएस-2021) को छत्तीसगढ़ राज्य शहरी विकास अभिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ष्टश्वह्व) नियुक्त किया गया है। उनके कार्यभार संभालने के बाद रिमिजियुस एक्का को एसयूडीए के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि वे संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर पहले की तरह बने रहेंगे। अनुपमा आनंद (आईएएस-2023), जो अभी सरायपाली (महासमुंद) में एसडीएम (राजस्व) हैं,उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत महासमुंद बनाया गया है।

नकटी मामले में कांग्रेस ने माना थाने का किया घेराव
पीएम-आवास तोड़े जाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग...29 जून को चला था बुलडोजर

रायपुर,09 जुलाई 2026। नया रायपुर के नकटी गांव में विस्थापन के दौरान कथित तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों को तोड़े जाने के मामले में कांग्रेस ने माना थाने का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस को आवेदन सौंपा। कांग्रेस का आरोप है कि विस्थापन की कार्रवाई के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों को भी तोड़ दिया गया। पार्टी का कहना है कि योजना के तहत बने घरों को नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की।

29 जून को हुई थी कार्रवाई : नया रायपुर के नकटी गांव में 29 जून को प्रशासन ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। इस दौरान कई मकानों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसके बाद मामला राजनीतिक विवाद का विषय बन गया। कांग्रेस लगातार इस कार्रवाई का विरोध कर रही है और प्रभावित परिवारों के पक्ष में आंदोलन कर रही है।

सरकार का दावा- पूरे गांव में नहीं, सिर्फ एक वार्ड में हुई कार्रवाई : इस मामले में वन मंत्री केदार कश्यप ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा था कि, पूरे नकटी गांव में नहीं, बल्कि सिर्फ एक वार्ड में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। उनके मुताबिक, प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कर उन्हें नया रायपुर में मकान भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। मंत्री ने कहा था कि 29 जून को केवल उस हिस्से में कार्रवाई हुई थी, जहां राजस्व विभाग की जमीन पर अतिक्रमण था। नकटी गांव के 17 वार्डों में से सिर्फ एक वार्ड में ही कार्रवाई की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित जमीन आज भी राजस्व विभाग के अधीन है।

कांग्रेस ने सरकार के दावे पर उठाए सवाल

सरकार के दावों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया था कि नकटी मामले में सरकार लगातार गलत जानकारी दे रही है। वहीं, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा था कि भाजपा सरकार अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए अलग-अलग बयान दे रही है। अब कांग्रेस ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग तेज करते हुए माना थाने में प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

तेंदूपत्ता संग्राहकों को सरकार का बड़ा तोहफा,162 करोड़ रुपये का बोनस जारी

रायपुर,09 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य की 621 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों से जुड़े 7 लाख 14 हजार 446 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 162.32 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) राशि का वितरण शुरू कर दिया गया है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार तेंदूपत्ता संग्राहकों, वनवासियों और आदिवासी परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि जंगल से जुड़े हर श्रमिक को उसके श्रम का उचित मूल्य समय पर मिले। उन्होंने बताया कि 3 जुलाई को सहकारिता सप्ताह और अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर वर्ष 2023 के तेंदूपत्ता संग्रहण की प्रोत्साहन राशि वितरण की शुरुआत की गई थी। भुगतान की प्रक्रिया तेजी से जारी है और जल्द ही सभी पात्र संग्राहकों के खातों में राशि पहुंच जाएगी। वन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी है। इससे संग्राहक परिवारों की आय में सीधा इजाफा हुआ है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि संग्रहण सत्र 2026 के दौरान प्रदेश के करीब 11.15 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को 734.25 करोड़ रुपये का संग्रहण पारिश्रमिक पहले ही ऑनलाइन माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजा जा चुका है। केदार कश्यप ने कहा कि सरकार संग्रहण से लेकर भुगतान तक पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, तकनीक आधारित और समयबद्ध बना रही है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा साईं ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)